{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
गुरुवार 23 जुलाई 2026
आषाढ़ शुक्ल 09 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 299
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	77,708.52
निफ्टी	-	24,238.50
सोना	-	1,51,698
चांदी	-	2,35,000
डॉलर	-	96.44

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

रिजर्व बैंक की योजनाओं से भारत में आए 21 अरब डॉलर

मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देश में अब तक 20.7 अरब डॉलर (करीब 21 अरब डॉलर) का विदेशी निवेश आया है। आरबीआई के अनुसार, इस राशि से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स) को मजबूती मिली है। इससे रुपये पर दबाव कम करने और बाहरी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। इस विशेष योजना में सबसे बड़ा योगदान एफसीएनआर (बी) जमा का रहा, जिसके माध्यम से 17.4 अरब डॉलर जुटाए गए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा उधारी और अन्य स्त्रोतों से भी उल्लेखनीय राशि प्राप्त हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

नई दिल्ली। भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है और इसके लॉन्च की तारीख भी तय कर ली गई है। हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे में जापानी शिंकानसेन तकनीक को पेश करेगी और मुंबई-अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। ये भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किमी लंबा है। बुलेट ट्रेन जब फुल स्पीड में होगी, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि अहमदाबाद से मुंबई के बीच औसतन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन अगले साल से दौड़ेगी। बता दें, फिलहाल सबसे हाई स्पीड ट्रेनों के जरिये मुंबई से अहमदाबाद के बीच यात्रा करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत के बाद यह दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल यात्रियों के कीमती समय की बचत होगी, बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढने़ वाली हैं।

5 राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज, बाकी सभी में यलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 48 घंटे में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं।

जंतर-मंतर पर फिर बवाल

छात्रों और पुलिस के बीच झड़प

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार रात छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। सीजेपीप्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए। जिसमें प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी लाठी दिख रही है। वो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे। उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था।

विपक्ष जितने घंटे चाहे सरकार चर्चा के लिए तैयार- जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम चाहते थे कि संसद में इस (पेपर लीक) पर चर्चा हो। चाहे कम समय की चर्चा हो या लंबी चर्चा, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय कर सकते हैं कि कितना समय लेना है। आप 12 घंटे ले सकते हैं, 18 घंटे ले सकते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर मेरा हमेशा से यह मानना ??रहा है कि विपक्ष जितने भी घंटे चर्चा के लिए तय करे, हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और बार-बार अपनी बात या शर्तें नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस समस्या को हल करने के बारे में सोचना चाहिए और संसद ही वह सबसे सही जगह है जहां हम इस पर गहराई से विचार कर सकते हैं। विपक्ष को चर्चा की अवधि तय करनी चाहिए, हर पहलू पर बात होनी चाहिए और हमें एक ठोस नीति बनानी चाहिए। बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं और देश का भविष्य भी हैं। देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सरकार और विपक्ष दोनों शामिल हैं। इसलिए, मैं विपक्ष से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह करता हूं; हम सभी को मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए और एक स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जेपी नड्डा ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में पेपर लीक हुआ, जहां सरकार में कांग्रेस साथ है। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस के सहयोग से सरकार है। तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बीएड का पेपर लीक हुआ। यहां भी विपक्ष की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक हुआ। पंजाब और केरल में भी पेपर लीक हुआ। कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ। ये कुछ नाम मैंने लिए हैं। इसकी लंबी फेहरिस्त है। मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं। आपने यूपीए और उसकी समर्थित सरकारों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की। ये साफ बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा हम प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ, सरकार से की तीन मांग...

प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन और पीएम मोदी मांगें माफी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन है। राहुल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाकाम बताते हुए कहा कि हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही साथ पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा करे और छात्रों के साथ हुए बर्बरातपूर्ण रवैये को लेकर पीएम मोदी भी माफी मांगे।

मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पेपर लीक की वजह से करोड़ों की संख्या में छात्रों और उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़ी है।

राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सरकार से पहली मांग ये कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी छात्रों की भी यही मांग है। मेरी दूसरी मांग ये है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार लोकसभा में चर्चा करें। ये देशहित से जुड़ा मुद्दा है और छात्रों का भविष्य अधर में जा रहा है। तीसरा और आखिरी मांग ये है कि छात्रों के साथ सरकार ने जो रवैया अपनाया है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफी मांगें। इन तीनों मांगों से हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं।

काले कपड़े पहन संसद पहुंचे सांसदों ने किया जोरदार प्रदर्शन

-पेपर लीक और शिक्षा की बदहाली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए संसद तक मार्च में छात्रों के साथ की गई बर्बरता के विरोध में बुधवार सुबह प्रमुख विपक्ष के सांसद काले लिवास पहन संसद पहुंचे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी सांसद नारे लगाते नजर आए।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही पेपर लीक और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वाला मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष ने संसद तक मार्च के दौरान युवाओं पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। मंगलवार को पीएम आवास के करीब कांग्रेस के धरने के दौरान राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद यह प्रदर्शन दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। जगह-जगह लोग प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इसे देखते हुए बुधवार सुबह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर अनेक सांसद काले लिवास में संसद पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है।

संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा लगातार गूंजा है। विपक्ष पेपर लीक के साथ ही देश की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसके अलावा अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। बताया जा रहा है कि इस कारण दिल्ली के बाहर भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अनेक प्रमुख शहरों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए आने की सुचनाएं आ रही हैं।

पीएम मोदी से पवार-सुले की मुलाकात... सत्ता गलियारे में चर्चा गर्म

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी, सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

यह मुलाकात तब हुई है जब एक दिन पहले शरद और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पहुंचकर सीजेपी और छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया था और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा भी की थी। संसद सत्र के दौरान हुई उच्च स्तरीय मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है, हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और पवार-सुले के बीच हुई बातचीत के विषय में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि सीजेपी का यह आंदोलन, जो 20 जून से लगातार जारी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। संगठन ने 20 जुलाई को संसद मार्च का प्रयास किया, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा-163 लागू कर दी। हजारों की संख्या में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 18 जुलाई से सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट होने के बाद भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं।

छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, चीफ जस्टिस बोले

वीडियो देखने का वक्त नहीं, हमारा समय बर्बाद न करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को एक वकील ने सीजेआई की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजेआई ने कहा कि हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने छात्र प्रदर्शन के दौरान निर्दोष छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि इस कार्रवाई में कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं।

दुआ मांगना, धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं- बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी राजनीतिक या चुनावी सभा में जीत के लिए की गई दुआ (प्रार्थना) अथवा आमीन कहना अपने आप में धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं हो सकता है। यह टिप्पणी मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट से एमईएमआईएम के विजेता उम्मीदवार शेख आसिफ रशीद की विधानसभा में चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी।

यह याचिका इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी के प्रत्याशी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने दायर की थी, जो शेख आसिफ रशीद से 162 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। खालिक ने याचिका में आरोप लगाया था कि रशीद ने इमाम के तौर पर अपनी पद का गलत फायदा उठाया। उन्होंने अपनी जीत के लिए दुआएं मांगी और नमाज में शामिल लोगों से अपनी विजय के लिए संकल्प लेने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर वोट मांगने जैसा था, और इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत रशीद की चुनावी जीत को अमान्य घोषित किया जाएं।

न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने केस के तथ्यों पर गौर कर कहा कि किसी सभा में दुआ करना या लोगों का आमीन कहना एक सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ति हो सकती है।

अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, आतंकवादी ने बेहद करीब से मारी गोली

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक संदिग्ध आतंकवादी भीड़भाड़ वाले बाजार में तैनात पुलिस दल के पास पहुंचता है और हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी पर बेहद करीब से गोली चला देता है। दिनदहाड़े हुए इस हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस दल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था। घटना अनंतनाग के लाल चौक क्षेत्र में दोपहर करीब साढ़े बारह बजे हुई। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर पुलिस दल के पास सामान्य तरीके से आता दिखाई देता है और अचानक गोलीबारी कर मौके से फरार हो जाता है। गंभीर रूप से घायल आशिक हुसैन कुरैशी को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है, ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की भी जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद घाटी में यह पहला बड़ा आतंकी हमला है। घटना के बाद पूरे अनंतनाग में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

अशोक बर्णवाल मप्र के नए मुख्य सचिव नियुक्त

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अमले में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को मध्य प्रदेश शासन का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (व्रष्ठ) द्वारा 22 जुलाई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, अशोक बर्णवाल

वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) के पद पर तैनात हैं। इसके साथ ही उनके पास भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अपर मुख्य सचिव और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है। अब उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें कि अनुराग जैन को नीति आयोग के सीईओ का प्रभार दिया गया है।

कुछ ना कहना

दल-बदल कानून की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार

-कपिल सिब्बल की याचिका पर 27 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल रोधी कानून) की व्याख्या पर पुनर्विचार की मांग करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका में विशेष रूप से दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-4 के तहत राजनीतिक दलों के विलय संबंधी प्रावधानों की व्याख्या स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं, के समक्ष सिब्बल ने कहा कि उन्होंने यह याचिका व्यक्तिगत क्षमता में दायर की है और इसे शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

सिब्बल ने अदालत से कहा कि याचिका इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न से जुड़ी है कि क्या संसद की संरचना उस प्रकार बदली जा सकती है, जैसा हाल के वर्षों में देखने को मिला है, और इस संदर्भ में दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-4 की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इसी विषय से संबंधित कुछ अन्य याचिकाएं भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। पीठ ने उनकी दलीलों पर विचार करते हुए मामले को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की सहमति दे दी।

दसवीं अनुसूची के तहत यदि किसी राजनीतिक दल का विधिवत विलय होता है तो सांसद या विधायक दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से बच सकते हैं। हाल के समय में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ सांसदों द्वारा विलय संबंधी प्रावधानों का हवाला देकर अन्य दलों में शामिल होने की घटनाओं के बीच यह याचिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ललित मोदी 16 साल बाद लौटेंगे भारत

-ईडी का जुर्माना रद्द; आईपीएल का पैसा विदेश भेजने का केस

नई दिल्ली। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने की तैयारी में हैं। एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई को आईपीएल 2009 के दक्षिण अफ्रीका आयोजन से जुड़े फेमा मामले में फैसला सुनाया था। इसमें मोदी को राहत देते हुए ईडी के लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था। फैसले के बाद ललित मोदी ने कहा कि अब उनकी भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है और वह इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर में बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद वह भारत आने की योजना बना रहे हैं। यह मामला 2009 में आईपीएल को भारत से दक्षिण अफ्रीका ले जाने से जुड़ा है। उस समय लोकसभा चुनाव के कारण सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट भारत से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया था। इसके आयोजन के लिए बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 243.45 करोड़ रुपए भेजे थे। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि यह रकम भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश भेजी गई, जिससे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ। ईडी ने 2011 में नोटिस जारी किया और 2018 में ललित मोदी समेत बीसीसीआई के कुछ पूर्व अधिकारियों पर जुर्माना लगाया था।

धन्यवाद

मान.राजकुमार करहि जी,
विधायक, लांजी-किरनापुर

आपके निरंतर प्रयासों से नांगझिरी बालाघाट रोड से राजमार्ग तक डामरीकृत पक्की सड़क निर्माण के लिए पूरक बजट 2026-27 में रू. 1करोड़ 29 लाख की स्वीकृति

ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक आभार

सरपंच
श्रीमति वर्षा विजय बारे
उपसरपंच, सचिव एवं समस्त पंच

ग्राम पंचायत बिसोनी

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से बिगड़ रही बाइकों की सेहत!

बाईक के इंजन में आ रही खराबी, बार बार मोटरसाइकिल सुधरवाने को मजबूर हो रहे वाहन चालक, चालकों की बढ़ी परेशानी, रिपेयरिंग दुकानों पर रोज लग रही लंबी कतारें , मिस्त्रियों का दावा- बाइकें एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के अनुरूप नहीं, बढ़ रहे इंजन फाल्ट

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर दोपहिया वाहन चालकों की परेशानियां ब ?ती ही जा रही हैं।नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई बाइक चालक शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल भरवाने के कुछ समय बाद उनकी मोटरसाइकिलों में इंजन में लगातार खराबी आ रही है और उन्हें बाईक सुधराने के लिए बार बार गैरेज ले जाना पड़ रहा है।जहा मोटरसाइकिल चालको द्वारा बाईक की आवाज बढ़ना, पिकअप कम होना, बार-बार बंद होना, स्टार्टिंग में दिक्कत और माइलेज घटने जैसी समस्याएं आ रही हैं। इन शिकायतों के चलते वाहन मालिकों को बार-बार मैकेनिक की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि मैकेनिक इससे खुश है और इंजन रिपेयरिंग करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करने वाले मिस्त्रियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इंजन संबंधी खराबियों वाले वाहनों की संख्या बढ़ी है। उनका दावा है कि विशेष रूप से बाइकों में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण फ्यूल सिस्टम, रबर पाइप, कार्बोरेटर और इंजन से जुड़ी दिक्कतें अधिक देखने को मिल रही हैं।हालांकि यह दावा उनके अनुभव पर आधारित लेकिन वाहन चालक और मिस्त्री दोनों ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के चलते वाहनों में दिक्कत आने की बात कह रहे हैं।

रिपेयरिंग दुकानों पर बढ़ रही भीड़

मोटरसाइकिल में लगातार परेशानी आने के चलते नगर के कई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकानों पर सुबह से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मिस्त्रियों के अनुसार पहले जहां सामान्य सर्विस के लिए वाहन आते थे, वहीं अब इंजन खोलने और फ्यूल सिस्टम टँकी की सफाई जैसे काम अधिक बढ़ गए हैं। इससे उनके काम और आमदनी दोनों में वृद्धि हुई है।

वाहन चालकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

बाइक मालिकों का कहना है कि बार-बार मरम्मत और पार्ट्स बदलवाने में हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पहले जिस बाइक में वर्षों तक कोई बड़ी समस्या नहीं आई, अब उसमें लगातार इंजन संबंधी शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे दैनिक आवागमन करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं।

उधर स्थानीय मोटरसाइकिल मिस्त्रियों का कहना है कि पुरानी तकनीक वाली कई मोटरसाइकिलें अधिक एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन के अनुरूप डिजाइन नहीं की गई थीं। ऐसे में फ्यूल लाइन, रबर सील और इंजन के कुछ हिस्सों पर अतिरिक्त असर देखने को मिल रहा है।

केवल एथनॉल ही नही हो सकती वजह

कुछ लोगो का मानना है पेट्रोल निर्धारित मानकों के अनुसार एथनॉल मिश्रण के साथ उपलब्ध कराया जाता है। सभी बाइकों में खराबी का कारण केवल एथनॉल नहीं माना जा सकता।टँकी में पानी जाने से भी फाल्ट आने की बात कही जा रही है।वही वाहन की उम्र, रखरखाव, ईंधन प्रणाली की स्थिति और निर्माता द्वारा स्वीकृत ईंधन का उपयोग भी महत्वपूर्ण कारक हैं।उनका मानना है कि यदि किसी वाहन में लगातार समस्या आ रही है तो अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराना उचित रहेगा।

उपभोक्ताओं की मांग

वाहन चालकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग और तेल कंपनियां इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं तथा यह स्पष्ट करें कि किन मॉडलों में किस स्तर तक एथनॉल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षित है। साथ ही यदि किसी विशेष तकनीकी समस्या की संभावना है तो उसके समाधान के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

एक नजर में

? एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के बाद बाइक चालकों की शिकायतें बढ़ीं

? इंजन मिसफायर, पिकअप कम होना और स्टार्टिंग में दिक्कत आम

? रोजाना रिपेयरिंग दुकानों पर पहुंच रही बड़ी संख्या में बाइकें

? मिस्त्रियों का दावा- पुरानी मोटरसाइकिलों के इंजन व पार्ट्स पर पड़ रहा असर

? उपभोक्ता बोले- बार-बार मरम्मत से बढ़ रहा खर्च,

? एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से, मिस्त्रियों की मौज

गाड़ी खराब होने की वजह बरसात नहीं, एथेनॉल है- दीपक चौरडिया

बैहर रोड स्थित एक मैकेनिक की दुकान में बाईक का इंजन खुलवा रहे वार्ड नंबर 9 निवासी दीपक चौरडिया ने बताया कि वे पिछले एक माह से काफी ज्यादा परेशान है। 3 से 4 बार उनकी गाड़ी खुल चुकी है, अभी फिर से उनकी गाड़ी का इंजन खोलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आने से टंकी का पेट्रोल पानी बन रहा है बार-बार वाहन खराब हो रहे हैं।वे स्वयं एक महीने में तीन से चार बार गाड़ी सुधराने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के पानी से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी एथेनॉल से है क्योंकि जब बरसात नहीं होती तब भी वाहन खराब होते हैं।

बीएस सिक्स गाड़ी भी एथेनॉल में चलने लायक नहीं है- रिजवान

बाइक मैकेनिक रिजवान खान ने बताया कि करीब ढाई माह से लगातार शिकायत आ रही है कि पेट्रोल की टंकी में पानी मिल रहा है, एथेनॉल मिक्स होने के चलते टंकी का पेट्रोल पानी बनकर खराब हो रहा है, जिससे हेड, वॉल, कार्बोरेटर और इंजन की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होने से पूरा पेट्रोल पानी बन रहा है, उससे वाल लीकेज हो रहे हैं आईसीएल खराब हो रही है।एथेनॉल पेट्रोल से उपभोक्ता परेशान है लेकिन हम जैसी मिस्त्रियों का बहुत फायदा हो रहा है।एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीएस सिक्स बाईक भी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने लायक नहीं है।इसलिए वाहन खराब हो रहे है।

राघवटोला आगजनी मामला में पुलिस कार्रवाई के विरोध में आदिवासी समाज, बोले दोषियों पर कार्रवाई करें, निर्दोषों को न फंसाएं

माइक्रो इरिगेशन प्लांट में आगजनी मामले में बढ़ती गिरफ्तारियों पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने रैली निकालकर, निष्पक्ष जांच की मांग

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। राघवटोला स्थित निर्माणाधीन माइक्रो इरिगेशन परियोजना प्लांट में 1 जुलाई को हुई करोड़ों रुपये की आगजनी की घटना के बाद पुलिस की लगातार जारी कार्रवाई अब विरोध के घेरे में आ गई है। मामले में पहले भाजपा नेता, जनपद पंचायत बालाघाट के निर्माण सभापति, ग्राम पंचायत के सरपंच सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य ग्रामीणों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने से आदिवासी समाज में

नाराजगी बढ़ गई है। 22 जुलाई को बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस कार्रवाई के विरोध में रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से पुरे मामले में बात करने बालाघाट पहुचे । ग्रामीणों ने मांग करी की मामले की निष्पक्ष जांच कर केवल वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा निर्दोष ग्रामीणों को परेशान करना तत्काल बंद किया जाए। मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण सबसे पहले स्थानीय बस स्टैंड पर एकत्र हुए। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम तक पैदल रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और ग्रामीण भी मौजूद रहे। पूरे समय प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिनके माध्यम से वे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शुभम उईके ने कहा कि आदिवासी समाज किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता और यदि आगजनी की घटना में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार पुलिस लगातार गांवों में पहुंचकर आदिवासी ग्रामीणों को हिरासत में ले रही है और पूछताछ के नाम पर कार्रवाई कर रही है, उससे पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बन गया है। उनका कहना था कि जिन लोगों का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें भी संदेह के आधार पर कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने इस पूरे मामले में सात से आठ लोगों की संलिप्तता की बात कही थी, लेकिन अब जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस खेतों में काम कर रहे किसानों और घरों में मौजूद आदिवासी ग्रामीणों को भी पूछताछ के लिए उठा रही है। इससे गांवों में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक में डर महसूस कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि वे पहले भी कई बार मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख चुके हैं और प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। लगातार पत्राचार और मांग के बाद 22 जुलाई को उन्हें पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया। यहां प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि जांच वैज्ञानिक साक्ष्यों और ठोस प्रमाणों के आधार पर की जाए, न कि केवल संदेह के आधार पर ग्रामीणों को आरोपी बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि राघवटोला में हुई आगजनी की घटना निश्चित रूप से गंभीर अपराध है और इसमें शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन कानून का उद्देश्य अपराधियों को सजा देना है, न कि निर्दोष लोगों को परेशान करना। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास पर्यात साक्ष्य हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी को जेल भेजना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि लगातार हो रही गिरफ्तारियों के कारण आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ रहा है। कई परिवारों के सदस्य कार्रवाई के भय से मानसिक तनाव में हैं। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई का असर गांवों के सामान्य जनजीवन पर भी पड़ रहा है और लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी समाज ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर वास्तविक दोषियों को ही कानून के दायरे में लाया जाए। साथ ही जिन ग्रामीणों का घटना से कोई संबंध नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

एजेंसी के संचालक गुलाबचंद पारधी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिले में गैस एजेंसियों की जांच अभियान के तहत सोमवार 21 जुलाई 2026 को विकासखंड किरनापुर के ग्राम मोहगांव खुर्द स्थित इंडेन ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी पर जांच की गई। जांच में गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी और अन्य अनियमितताएं मिलने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.के. भलावी के निर्देशन में गठित जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी.एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी किरनापुर शामिल रहे। जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टॉक में गंभीर अंतर पाया गया। 68 खाली सिलेंडर अधिक तथा 55 भरे सिलेंडर कम मिले। इसी प्रकार 5 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडरों में 29 खाली एवं 34 भरे सिलेंडर कम पाए गए। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडरों में 30 खाली सिलेंडर कम तथा 23 भरे सिलेंडर अधिक मिले। इसके अलावा 5 किलोग्राम के एफटीएल गैस सिलेंडर पांच कम तथा 10 किलोग्राम एक्स्ट्रालाइट के दो खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा राइस मिल परिसर से लगी दुकान के एक कक्ष में गोदाम के अतिरिक्त अनधिकृत स्थान पर 14.2 किलोग्राम के 83 भरे एवं 19 खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम के पांच खाली सिलेंडरों का भंडारण किया गया था। जांच दल ने प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता, स्टॉक का नियमित संधारण नहीं किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन माना। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर मौके पर पंचनामा, जब्ती एवं सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई। इस संबंध में इंडेन गैस एजेंसी के प्रोपराइटर गुलाबचंद पारधी तथा मौके पर उपस्थित उनके भाई सालिगराम पारधी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत महिला थाना पुलिस ने छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

पांच विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नशे से दूरी है जरूरी 2.0अभियान के तहत 22 जुलाई को महिला थाना बालाघाट पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। अभियान के अंतर्गत महिला थाना पुलिस ने द बालाघाट पब्लिक स्कूल, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल, महात्मा गांधी नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री दादाबाड़ी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल तथा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर भमोड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ ही यह परिवार, समाज और भविष्य के लिए भी घातक साबित होती है। विद्यार्थियों से न केवल स्वयं नशे से दूर रहने, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई। पुलिस ने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि यदि कहीं नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार या नशे से संबंधित कोई गतिविधि दिखाई दे, तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ताकि समय

रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की शपथ ली। महिला थाना प्रभारी किरण वरकड़े ने बताया कि नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले में लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो।

नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत भरवेली पुलिस ने चलाया जनजागरूकता अभियान

सब्जी बाजार और स्कूलों में चौपाल लगाकर युवाओं और नागरिकों को दिलाई नशामुक्त समाज बनाने की शपथ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। प्रदेशभर में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत भरवेली थाना पुलिस द्वारा बुधवार को व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के अंतर्गत भरवेली के अटल सब्जी बाजार परिसर सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में चौपाल लगाकर लोगों और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागिता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पन्द्रों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अटल सब्जी बाजार परिसर में व्यापारियों, आम नागरिकों एवं युवाओं से संवाद किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब, गांजा, नशीली दवाओं और अन्य मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बल्कि परिवार, समाज और भविष्य को भी प्रभावित करता है। उन्होंने नागरिकों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। इसी क्रम में पुलिस टीम ने रवींद्रनाथ टैगोर इंग्लिश स्कूल भरवेली तथा शासकीय माध्यमिक शाला, पाथरवाड़ा में भी चौपाल आयोजित की। यहां विद्यार्थियों को नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें जीवन में अनुशासन, शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाकर नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई।पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में हो या अवैध रूप से नशीले पदार्थों का कारोबार करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ताकि समाज को

नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों और विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।इस जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पन्द्रों एवं भरवेली थाना पुलिस की टीम की सराहनीय भूमिका रही।

बारबेड वायर (कांटेदार तार)
एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरुपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोनः- 07632-243531
मोः- 8989976858, 9425139998

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

बाड़ी विवाद में दो भाई ने लाठी-कुल्हाड़ी से किये हमला-पति-पत्नी गंभीर घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छतेरा में बाड़ी के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों ने अपने पड़ोसी दंपती पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। दोनों घायल लता पति राजेंद्र ठाकरे 44 वर्ष और राजेंद्र पिता हना जी ठाकरे 46 वर्ष का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम छतेरा निवासी राजेंद्र ठाकरे 46 वर्ष खेती किसानी करते हैं। आरोप है कि उनके घर के सामने ही पड़ोसी राजेंद्र राहंगडाले और उसका भाई मुन्ना राहंगडाले ने अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा मकान बना रखा है। राजेंद्र ठाकरे ने घर के पास अपनी बाड़ी की रुधान बनाई हुई है। इसी बाड़ी को तोड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। राजेंद्र ठाकरे के अनुसार 21 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे राजेंद्र और मुन्ना राहंगडाले उनके घर आए और बाड़ी तोड़ने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर दोनों भाई गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान राजेंद्र की पत्नी लता पति राजेंद्र ठाकरे भी वहां पहुंच गईं। आरोप है कि दोनों भाइयों ने बाड़ी नहीं तोड़ने पर ट्रैक्टर चलाकर जान से मारने की धमकी दी और लाठी व कुल्हाड़ी से राजेंद्र और लता के सिर पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों के बीच-बचाव के बाद घायल दंपती लालबर्रा थाना पहुंचे। पुलिस ने तत्काल दोनों को लालबर्रा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया।फिलहाल घायल राजेंद्र और लता ठाकरे का जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार चल रहा है। इस मामले की जांच पड़ताल लालबर्रा पुलिस द्वारा की जा रही है।

कागजों में उलझा बचपन, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से स्कूल जाने से पहले ही रुकी बच्चों की पढ़ाई

जनसुनवाई में छलका परिजनों का दर्द, कहीं माता-पिता के निधन से अनाथ बच्चों के दस्तावेज अटके, तो कहीं 15 साल से मध्यप्रदेश में रहने के बावजूद बेटियों का नहीं बन रहा प्रमाण पत्र

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

सरकार लगातार शिक्षा के अधिकार, हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने और छात्र-छात्राओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के दावे कर रही है, लेकिन जिले में सरकारी दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया अब कई बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद स्कूलों में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अनिवार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं दस्तावेजों के अभाव में कई बच्चों का प्रवेश अधर में लटक गया है। जिला मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ऐसे ही दो मामले सामने आए, जहां परिजनों ने बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए जिला कलेक्टर से गुहार लगाई।

पहला मामला बैहर तहसील के गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंडी का है, जहां वृद्ध महिला अपने दो नाती-नातिन जासमीन मसराम और जावेन्द्र मसराम के साथ न्याय की उम्मीद लेकर जनसुनवाई पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि करीब छह वर्ष पहले दोनों बच्चों के माता-पिता का निधन हो चुका है। तब से वह स्वयं दोनों बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं। माता-पिता के निधन के बाद बच्चों का आधार कार्ड तक नहीं बन सका, जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अब स्कूल में प्रवेश के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों के अभाव में दोनों बच्चों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। संदीप मसराम ने बताया कि वह कई बार तहसील कार्यालय और संबंधित राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। आवेदन भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि उपलब्ध जन्म प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेखों

के आधार पर बच्चों का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज शीघ्र तैयार कराए जाएं, ताकि दोनों बच्चे समय पर स्कूल में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनका कहना था कि माता-पिता को खोने के बाद अब यदि सरकारी प्रक्रियाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई भी छिन गई तो उनके भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। जनसुनवाई में दूसरा मामला तिरोड़ी क्षेत्र के महकेपार गांव से सामने आया, जहां संजय डोंगरे अपनी दो बेटियों मुस्कान डोंगरे और मानसी डोंगरे के जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका परिवार लगभग 15 वर्ष पहले महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश आकर बस गया था और तब से लगातार यहीं निवास कर रहा है। उनके पास मध्यप्रदेश में निवास से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटियों का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। संजय डोंगरे ने आरोप लगाया कि पटवारी द्वारा 45 वर्ष पुराना राजस्व रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। उनका कहना है कि 15 वर्षों से मध्यप्रदेश में रहने और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद आवेदन का सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी दोनों बेटियों का जाति प्रमाण पत्र लंबित पड़ा है। बड़ी बेटी मुस्कान हाईस्कूल की छात्रा है, जबकि छोटी बेटी भी विद्यालय में अध्ययनरत है। स्कूल द्वारा जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है, लेकिन दस्तावेज नहीं बनने से दोनों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और छात्रवृत्ति सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जनसुनवाई में पहुंचे दोनों परिवारों का कहना था कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन जब आवश्यक दस्तावेज ही समय पर नहीं बनेंगे तो सबसे अधिक नुकसान उन मासूम बच्चों का होगा, जिनका इस पूरी प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जल्द तैयार हो सकें। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे परिजनों की पीड़ा सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके सामने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। उनका कहना था कि यदि समय रहते प्रमाण पत्र नहीं बने तो बच्चे स्कूल में प्रवेश, छात्रवृत्ति और शासन की अन्य योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कागजी औपचारिकताओं से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दी जाए, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा केवल दस्तावेजों के अभाव में अधूरी न रह जाए।

प्रशासन से लगाई त्वरित समाधान की गुहार

दोनों मामलों में परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए दस्तावेजी प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जाति, निवास एवं अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग की। जनसुनवाई में पहुंचे परिजनों का कहना था कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि आवश्यक प्रमाण पत्र ही समय पर नहीं बन पाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन मासूम बच्चों को होगा, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की अपील की।

टला बड़ा हादसा-बूढ़ी रोड पर गिरा वर्षों पुराना विशाल पीपल का पेड़

बाल-बाल बची 2 लोगों की जान, कार क्षतिग्रस्त होने से बची, घंटों बाधित रहा यातायात, दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें, विद्युत तार टूटने से बिजली व्यवस्था प्रभावित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर के बूढ़ी रोड पर बुधवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब करीब 60 से 100 वर्ष पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस पेड़ की चपेट में आने से 2 लोग बच गए, वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार क्रमांक एमपी 49सी 4935 भी क्षतिग्रस्त होने से बच गई। इस तरह यहां एक बड़ा हादसा टल गया।उधर घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पेड़ गिरते ही जोरदार आवाज हुई, जिससे आसपास मौजूद लोग घबरा गए। कुछ ही सेकंड का अंतर होने के कारण सड़क स्थानीय दो लोग सुरक्षित बच गए। यदि वे कुछ कदम आगे बढ़ गए होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

महज 500 मीटर दूर नपा, कर्मचारियों को पहुंचने में लग गया 3 घंटे से अधिक का समय

जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण, जहां जर्जर भवनों से जान का जोखिम बना है, वहीं दशको पुराने पेड़ भी धराशाही हो रहे है।बुधवार को सुबह बस स्टैंड से लगे चर्च के पास वर्षो पुराना एक पीपल का पेड़ धराशाही हो गया। यह तो अच्छा रहा कि सुबह का समय होने से मार्ग पर आवागमन ज्यादा नहीं था, अन्यथा किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। चूंकि बस स्टैंड के पास ही यह क्षेत्र पड़ता है और इस मार्ग में आवागमन भी ज्यादा है।उधर पेड़ गिरने की घटना के तीन घंटे बाद भी नगरपालिका को अमला नहीं पहुंचा। जिससे सड़क पर गिरे पेड़ के कारण, बुढ़ी मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। किसी तरह लोग गिरे पेड़ के नीचे बने गेप से दुपहिया वाहन लेकर निकले तो स्कूली बच्चों को भी जोखिम उठाकर रास्ता पार करना पड़ा।चिंतनीय बात यह है कि नगरपालिका से महज 500 मीटर की दूरी पर पेड़ गिरा है, बावजूद इसके, घंटो बाद भी नगरपालिका का अमला, घटनास्थल नहीं पहुंच सका।

आवागमन हुआ प्रभावित

उधर इस घटना के कारण बूढ़ी से बस स्टैंड तथा बस स्टैंड से बूढ़ी की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। सुबह का समय होने के कारण कर्मचारी, व्यापारियों, आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्कूली बच्चे समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सके, जबकि रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा।

जान जोखिम में डालकर पेड़ के नीचे से गुजरते रहे लोग

उधर सबसे चिंताजनक बात यह रही कि सड़क पर विशाल पेड़ गिरने के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पेड़ के नीचे से निकलते रहे। स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कई लोग जल्दबाजी में खतरा उठाकर आवागमन करते रहे। इससे किसी भी समय दूसरा हादसा होने की आशंका बनी रही।

तार टूटने से चरमराई विघुत व्यवस्था

उधर पेड़ गिरने के साथ ही वहां से गुजर रही विद्युत लाइनें भी टूट गईं, जिससे आसपास के क्षेत्र की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई। बिजली के तार सड़क पर गिरने से खतरा और बढ़ गया। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत आपूर्ति बंद कर स्थिति को सुरक्षित बनाया। जिसके कारण घन्टो बिजली गुल रही।

पेट काटकर बनाई गई आवागमन व्यवस्था

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन, नगर पालिका और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने मशीनों और कटर की मदद से विशाल पेड़ को काटकर हटाने का कार्य शुरू किया। करीब तीन से चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया जा सका, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।

करीब 60 से 100 साल पुराना बताया जा रहा पेड़

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पीपल का पेड़ लगभग 60 से 100 वर्ष पुराना था। लंबे समय से इसकी जड़ें कमजोर होने और पेड़ के झुकाव की शिकायतें सामने आ रही थीं। लोगों ने मांग की है कि शहर के पुराने और जर्जर हो चुके बड़े पेड़ों का सर्वे कराया जाए, ताकि समय रहते उनकी छंटाई या आवश्यक कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। सौभाग्य से इस बार किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन यदि पेड़ कुछ मिनट पहले या अधिक व्यस्त समय में गिरता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल यातायात बहाल कर दिया गया है और संबंधित विभाग क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सामान्य करने में जुटा हुआ है।

हमे लगा कि भूकम्प आ गया- नितिन सोनी

प्रत्यक्षदर्शी नितिन सोनी ने बताया कि वह राजेश सिंग के साथ खड़ा थे। इसी दौरान पेड़ धीरे से गिरते हुए दिखा, हमें लगा की भूकंप आ गया है। जिसके बाद हम वहां से हटे, अन्यथा हम दो लोगों को जान का जोखिम हो सकता था।

नपा नही दे रही ध्यान-अनिल सोनी

नपा पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि पेड़ गिरने को, तकरीबन 3 घंटा हो गया है, लेकिन अब तक इसे हटाने नगरपालिका का कोई अमला नहीं पहुंचा है। जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और लोगो को परेशानी हो रही है। घटना के बाद विद्युत विभाग का अमला पहुंचा और क्षेत्र की बिजली बंद कर दी है।नपा ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द आवागमन व्यवस्था बहाल करनी चाहिए।

बैल की तलाश में जंगल पहुंचा किसान-मादा भालू से हुई आमने सामने की भिड़ंत

15 मिनट तक मौत से जूझता रहा किसान
हाथ पैर नोचने के बाद शावकों को लेकर जंगल में भागा भालू

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम धीरी में बुधवार की सुबह एक किसान की बहादुरी ने उसे मौत के मुंह से वापस लौटा दिया। जंगल में बैल की तलाश कर रहे किसान का अचानक दो शावकों के साथ मौजूद मादा भालू से सामना हो गया। अपने बच्चों को खतरा महसूस होते ही भालू ने किसान पर जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन किसान ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई और करीब 15 मिनट तक भालू से संघर्ष करता रहा। आखिरकार भालू अपने दोनों शावकों को लेकर जंगल में भाग गया। हालांकि इस संघर्ष में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया घायल किसान बिदरुसिंह पिता खेलसिह टेकाम 53 वर्ष को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिदरुसिंह टेकाम ग्राम धीरी निवासी खेती किसानी करते है। 22 जुलाई की सुबह बिदरुसिह जब घर से मवेशी निकाल रहा था। इसी दौरान एक बैल रस्सी छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। बैल को पकड़ने के लिए बिदरुसिंह उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। गांव से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही उसकी नजर अचानक दो शावकों के साथ मौजूद मादा भालू पर पड़ी। इससे पहले कि वह संभल पाता भालू ने उस पर हमला कर दिया।हमले के दौरान बिदरुसिह ने साहस का परिचय देते हुए भालू के अगले दोनों पैर पकड़ लिए। इसके बाद जंगल के बीच दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। भालू ने अपने पंजों और दांतों से बिदरु सिह पर लगातार हमले किए। बचाव के दौरान बिदरूसिह के दोनों हाथ भालू के जबड़ों में आ गए और पंजों से उसके हाथ पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। जान बचाने के लिए उसने पास के एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन भालू ने उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद भी बिदरूसिह संघर्ष करता रहा।करीब 15 मिनट तक चले इस संघर्ष के बाद अचानक भालू अपने दोनों शावकों को लेकर जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल बिदरुसिह किसी तरह जंगल से बाहर निकला और गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में ग्रामीणों ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और तत्काल घर पहुंचाकर परिजनों को सूचना दी।

परिजन घायल बिदरूसिह को गढ़ी के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बैहर अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उसके हाथ पैर के गहरे घावों पर टांके लगाए हैं। बिदरूसिह को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है।घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला भी जिला अस्पताल पहुंचा और घायल बिदरूसिह कुछ राहत राशि भी प्रदान की है। गढ़ी वन परिक्षेत्र का अधिकांश इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ है। जंगल से लगे गांवों में भालू, तेंदुआ और अन्य वन्यप्राणियों की आवाजाही आम बात है। जिनसे मानव और वन्यप्राणी संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। पूर्व में भी इस क्षेत्र में वन्यप्राणियों के हमलों में कई लोग घायल हो चुके हैं। जबकि कुछ मामलों में जनहानि भी हुई है।

जागपुर की बेटी छाया बिसेन बनीं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्षेत्र में खुशी की लहर

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शहर से लगे ग्राम जागपुर के लिए गर्व का क्षण उस समय आया, जब गांव की बेटी छाया (दिव्या) बिसेन का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और शुभचिंतकों ने इसे न केवल बिसेन परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। छाया (दिव्या) बिसेन, ग्राम जागपुर निवासी पीतम बिसेन की सुपुत्री हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन के बल पर यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनकी नियुक्ति से यह साबित हुआ है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीणों ने कहा कि छाया (दिव्या) की यह उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इससे अन्य छात्राओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी। ग्रामीणों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मिली यह सफलता पूरे गांव के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर परिजनों, मित्रों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने छाया (दिव्या) बिसेन को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी सेवाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर अपने परिवार, गांव और जिले का नाम आगे भी रोशन करेंगी।

जिला पुलिस पेंशनर संघ की मासिक बैठक सम्पन्न

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला पुलिस पेंशनर संघ की मासिक बैठक बुधवार को शहर के बूढ़ी स्थित एक होटल में संपन्न की गई। बैठक में संघ करीब 23 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। संघ के नरेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि बैठक के दौरान सभी उपस्थित जनों को नशे के दुष्परिणामो से अवगत कराकर नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया गया। इसी तरह संघ के ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में नौकरी में अतिरिक्त कार्य किया है। उनसे एरियर के लिए आवेदन लिए गए। जिसे डीपीसी के समक्ष प्रस्तुत कर एरियर की मांग की जाएगी।बैठक में महत्वपूर्ण यह रहा कि

सभी पेंशनरों को एसबीआई बैठक की सीपीपी योजना व एप की जानकारी देकर उसके फायदे बताए गए। आगामी दिनों में एक भव्य कार्यक्रम किए जाने को लेकर भी चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रमुख रूप से संभागीय उपाध्यक्ष नेमीचंद सोनेकर, जिलाध्यक्ष उमेशचंद प्रजापति, प्रभारी अध्यक्ष नरेन्द्र ड्क्ससह परिहार, दिलीप पंचेश्वर, अशोक डहाके, कलीराम परते, दुर्गा प्रसाद बिसेन, राजेन्द्र बम्हुरे, नरेन्द्र दुबे, रमेश इंगले, कमलकांत साहू, सविता, मुन्नालाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

हाई स्कूल मार्ग शिवाजी चौक के समीप बने बड़े-बड़े गड्ढे, हादसों को दे रहे न्यौता, जिम्मेदार मौन

स्कूली बच्चों एवं राहगीरों को हो रही परेशानी, बड़ी दुर्घटना होने की बनी संभावना, सड़क का मरम्मत करवाने की उठी मांग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय के अति व्यस्त और मुख्य मार्ग स्थित शिवाजी चौक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के समीप सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढे रोजाना हादसों को न्योता दे रहे हैं। यह मार्ग न केवल स्कूली बच्चों के लिए, बल्कि पूरे नगर की आवाजाही का मुख्य केंद्र है। प्रशासन की अनदेखी के चलते इस मार्ग से गुजरने वाले छात्र-छात्राओं एवं राहगीरों व स्थानीयजनों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जबकि इस मार्ग से रोजाना अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता है बावजूद उसके उन्हे स्कूल के समीप सड़क के बीच में जगह-जगह बने गड्ढे दिखाई नही दे रहे है जो समझ से परे लग रहा है। जबकि इस समस्या से कई बार सड़क विभाग को भी अवगत करवा दिया गया है लेकिन उनके द्वारा भी कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। राहगीर एवं स्थानीयजनों ने शासन-प्रशासन से हाई स्कूल मार्ग शिवाजी चौक के समीप सहित अन्य स्थानों पर सड़क के बीच में बने गड्ढों एवं सड़क का जल्द मरम्मत कार्य करवाने की मांग की है।

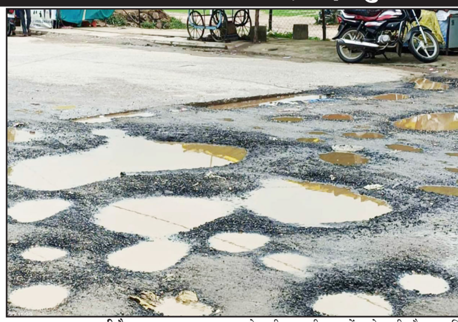

प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क

आपकों बता दे कि हाई स्कूल मार्ग के लालबर्रा बस स्टैण्ड से शिवाजी चौक तक विगत वर्ष पूर्व टु वे सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया है, उसके बाद से अधुरा छोड़ दिया गया है। वहीं सीमेन्टीकरण सड़क की सीमा के बाद से डामरीकरण सड़क खराब हो चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे बन गये है, इन गड्ढों में बारिश होने पर पानी जमा हो जाने से आवागमन करने वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को रही है। जबकि यह मार्ग नगर की जीवनरेखा माना जाता है। इसी मार्ग पर शिवाजी चौक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा शासकीय अस्पताल, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, कॉलेज और अन्य प्रमुख शासकीय कार्यालय स्थित हैं। दिनभर अधिकारियों, मरीजों, विद्यार्थियों और आम जनता की भारी आवाजाही इस सड़क पर बनी रहती है। बावजूद इसके सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर किसी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों में जलभराव होने से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। स्कूल आने-जाने वाले छोटे-छोटे ब%चे अक्सर इन छिपे हुए गड्ढों में फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे न केवल उन्हें चोट लग रही है, बल्कि पानी और कीचड़ के छीटों से उनकी ड्रेस एवं बैग भी खराब हो रहे हैं। कई बार तेज रफ्तार वाहनों के गुजरने से गड्ढों का गंदा पानी पैदल चल रहे ब'चों और राहगीरों पर उछल जाता है। साथ ही गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जिससे लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

दुर्घटना को खुला आमंत्रण

स्थानीयजनों और अभिभावकों का कहना है कि हाई स्कूल मार्ग शिवाजी चौक के पास बने ये गड्ढे कभी भी किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकते हैं। दुपहिया वाहन चालक अक्सर असंतुलित होकर गिर रहे हैं। रात के समय रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण खतरा दोगुना हो जाता है। साथ ही स्कूल के समीप इस तरह के जानलेवा गड्ढे होना प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। यदि समय रहते इन गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाई गई, तो किसी भी समय बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इसलिए सड़क विभाग से मांग है कि हाई स्कूल मार्ग शिवाजी चौक एवं अन्य स्थानों पर सड़क में जगह-जगह बने गड्ढों का जल्द मरम्मत कार्य करवाये ताकि आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

गड्ढों का जल्द मरम्मत कार्य करवाये प्रशासन - भाऊराम

जिला कांग्रेस कमेटी सचिव, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर ने बताया कि लालबर्रा हाई स्कूल मार्ग एक व्यस्तम मार्ग है और इस मार्ग पर ब्लाक का सबसे बड़ा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय स्थित है एवं अन्य शासकीय कार्यालय भी है। साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय में हजारों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है लेकिन स्कूल के समीप ही सड़क के बीच में बड़े-बड़े गड्ढे बन गये है और गड्ढों में पानी एवं कीचड़ होने से स्कूली बच्चों के साथ ही इस मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री गाड़ेश्वर ने बताया कि यह मार्ग लालबर्रा मुख्यालय को ग्राम बघोली, टेकाड़ीला सहित अन्य दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला एक मुख्य संपर्क मार्ग है और इस मार्ग से 24 घंटे आवागमन जारी रहता है। लेकिन सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आये-दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही दुपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों के गिरने और चोटिल होने का डर हमेशा बना रहता है। प्रशासन से मांग है कि हाई स्कूल मार्ग के शिवाजी चौक के सामने, उत्कृष्ट विद्यालय के समीप एवं अन्य स्थानों पर सड़क में बने गड्ढों का जल्द मरम्मत कार्य करवाये ताकि आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

बालाघाट-सिवनी हाईवे मार्ग बिरसोला के पास गिरा विशालकाय पेड़, बड़ा हादसा टला

बीच सड़क में पेड़ गिरने से आवागमन रहा बाधित, कड़ी मशक्कत के बाद सुबह हटाया गया पेड़, आवागमन हुआ बहाल

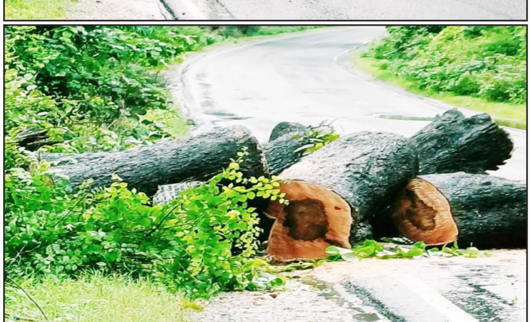

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। बालाघाट-सिवनी हाईवे मार्ग स्थित ग्राम पंचायत बिरसोला के समीप बीते मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात्रि में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच अचानक सड़क किनारे लगा एक विशालकाय पेड़ भरभराकर मुख्य मार्ग पर धराशायी होकर गिरा। गनीमत यह रही कि जिस समय यह पेड़ गिरा, उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। वहीं विशालकाय पेड़ हाईवे मार्ग के बीच में धराशायी होकर टूटकर सड़क के बीच में गिर जाने के कारण रात्रि में इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। जिसके चलते दोनों ओर चौपहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई और बुधवार की सुबह ग्रामीणजनों की मदद से सड़क के बीच में गिरे पेड़ को हटाया गया। जिसके बाद आवागमन बहाल हुआ।

सुनसान मार्ग पर हुई घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 21 जुलाई की दरमियानी रात्रि की है। बालाघाट-सिवनी मार्ग जिले के अति व्यस्ततम हाईवे में गिना जाता है। इस मार्ग से दिन-रात दर्जनों बसें, भारी ट्रक और निजी चौपहिया, दुपहिया वाहन गुजरते हैं। देर रात मार्ग सुनसान होने के कारण जब बिरसोला के समीप विशालकाय पेड़ गिरा, तब कोई भी वाहन इसके संपर्क में नहीं आया। अगर वाहन से उस समय कोई गुजरते रहते तो वे पेड़ की चपेट में आ सकते थे, जिससे बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था लेकिन रात्रि में विशालकाय पेड़ टूटकर गिरने एवं सुनसान मार्ग होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि यह घटना दिन के समय या किसी वाहन के गुजरते समय होती, तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। वहीं रात में पेड़ गिरने की वजह से मुख्य सड़क पूरी तरह से अवरूध्द हो गई थी, जिससे सुबह आने-जाने वाले वाहनों के पहिए थम गये और दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने लगीं। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह संबंधित प्रशासनिक अमला और लोक निर्माण विभाग एवं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से कुल्हाड़ी एवं कटर मशीनों की मदद से विशालकाय पेड़ की शाखाओं को काटकर सड़क से अलग किया गया। बुधवार की सुबह कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से पेड़ को हटाकर यातायात को पुनः सुलभ करवाया गया। जिसके बाद बालाघाट से सिवनी हाईवे मार्ग से आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। स्थानीय ग्रामीणों एवं राहगीरों ने प्रशासन से मांग की है कि मानसून के मौसम को देखते हुए हाईवे के दोनों ओर लगे पुराने और जर्जर पेड़ों की छटाई की जाये ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से किसी अनहोनी को रोका जा सके।

निबंध, पोस्टर, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया नशे के प्रति जागरूक

महाविद्यालय में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में उ'च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अन्तर्गत नशा उन्मूलन गतिविधियों के तहत मंगलवार को महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निबंध, पोस्टर, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उक्त प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के प्रति जागरूक भी किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थी रविना सराड़े ने प्रथम, रिया नागेश्वर ने द्वितीय, सलमा शेख ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह पोस्टर प्रतियोगिता में संध्या ऐसने ने प्रथम एवं संजना पंचेश्वर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रंगोली प्रतियोगिता में स्वेता सहारे ने प्रथम, सरिता बोरिकर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में दामिनी बोपचे ने प्रथम हासिल किया है। वहीं समस्त प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने नशामुक्ति का प्रभावी संदेश दिया। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के साथ समाज को नशामुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. संगीता मेश्राम, कार्यक्रम प्रभारी डॉ. प्रदीपकुमार भिमटे, सुमन बरवा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार खण्डायत, डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम, डॉ. देवराज चौरे, श्रीमती संध्या भलावे, श्रीमती भूमेश्वरी ठाकरे, मनीष शिवहरे, डॉ. आशा कारे, श्रीमती अनिभा शरणागत, डॉ. आरती विश्वकर्मा, दीपक अहिरवार, पीतम मुरते, व्यंकट नगपुरे, श्रीमती सरिता एड़े, रामदयाल मथारे, लकेश गेडाम, मिनेश पंचेश्वर, प्रसिक हुमनेकर, निशांत तलवरे एवं छात्र-छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

खारा की गैस एजेंसी में पायी गई स्टॉक की गड़बड़ी,

संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस. के. भलावी के मार्गदर्शन में जिले में गैस एजेंसियों की जांच अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 21 जुलाई 2026 को विकासखंड किरनापुर के ग्राम खारा स्थित पारधी भारत गैस ग्रामीण वितरक एजेंसी का औचक निरीक्षण किया गया। जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी. एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश श्रीवास्तव (बैहर), मिलन तिवारी (किरनापुर) तथा श्रीमती निहारिका अवस्थी (वारासिवनी) शामिल थीं। निरीक्षण के दौरान एजेंसी के गैस स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों में 47 खाली सिलेंडर अधिक तथा 37 भरे सिलेंडर कम पाए गए। वहीं 5 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर अधिक और 5 भरे सिलेंडर कम मिले। इसके अलावा 5 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर कम तथा 3 भरे सिलेंडर अधिक पाए गए।

जांच के समय एजेंसी के प्रोपराइटर श्री महेश कुमार पारधी मौके पर अनुपस्थित थे। उन्हें दूरभाष के माध्यम से सूचना देने के बावजूद वे जांच स्थल पर नहीं पहुंचे। इसके बाद एजेंसी प्रबंधक, ऑपरेटर एवं कर्मचारी श्री अरुण ठाकरे की उपस्थिति में संपूर्ण जांच कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता तथा गैस स्टॉक के रखरखाव एवं संधारण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया। जांच दल ने मौके पर ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एजेंसी के प्रोपराइटर एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

शिक्षा में भ्रष्टाचार और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन आज

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और शिक्षा व्यवस्था में पनप रहे भ्रष्टाचार के विरोध में राजाभोज जैविक/प्राकृतिक कृषि उपज मंडी काम्पलेक्स परिसर में विद्यार्थियों के द्वारा 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से एक विशाल एवं शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को थोपे जाने, शिक्षा के निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी तथा निरंतर हो रहे पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई जायेगी। चर्चा में आयोजक छात्रों ने बताया कि शिक्षा में भ्रष्टाचार और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन किया जा रहा है यह आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बल्कि दलगत राजनीति से परे हटकर पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से छात्र हित और छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। आगे बताया कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि छात्रों का मौलिक अधिकार है। वर्तमान नीतियों से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इस प्रदर्शन के जरिएसरकार और प्रशासन से छात्र विरोधी नीतियों को वापस लेने तथा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की मांग की जायेगी। इस अवसर पर क्षेत्र के समस्त छात्र-छात्राओं, युवाओं एवं नागरिकों से आयोजक विद्यार्थियों ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होवें और छात्र एकता का परिचय देते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई में अपनी सहभागिता दर्ज कराये।

नहर में झाड़ियो और गंदगी से पानी हुआ अवरुद्ध

मेहंदीवाड़ा के किसान परेशान रोपाई पिछड़ने से आक्रोश

पद्मेश न्यूज।वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा से गुज़रने वाली ढूंटी नहर का लाभ किसानों को मिलता नज़र नहीं आ रहा है। मुख्य नहर से निकलने वाली छोटी नहर में पानी नही पहुँचने के कारण क्षेत्र के किसानों के सामने खेती किसानी का संकट खड़ा हो गया है। किसान रोपाई और परहा लगाने के लिए पानी की राह तक रहे हैं लेकिन नहर की जर्जर स्थिति और विभागीय अनदेखी उनकी प्रतीक्षा को और लंबा खींच रही है।

जर्जर स्थिति और झाड़ियो के कारण अवरुद्ध हुआ पानी

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मेहंदीवाड़ा में किसानों ने खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में परहा लगाने के लिए मुख्य नहर से निकलने वाली छोटी नहर में पानी की सख्त आवश्यकता है। परंतु इस छोटी नहर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। मुख्य नहर से सड़क के दूसरे छोर तक यद्यपि लाइनिंग का कार्य तो किया गया था लेकिन देख रेख के अभाव में वह पूरी तरह मिट्टी, गाद और गंदगी के नीचे दब चुका है। स्थिति यह है कि इपक्का निर्माण अब दिखाई तक नहीं दे रहा है। किसानों का आरोप है कि बीते दिनों प्रशासन के द्वारा झाड़ियों की कटाई.छंटाई नही कराई गई जिससे नहर के भीतर जमा मिट्टी और गाद को बाहर निकालने की ज़हमत किसी ने नहीं उठाई। इतना ही नहीं जिस आउटलेट से मुख्य नहर का पानी छोटी नहर में प्रवेश करता है वहाँ भी भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य नहर में भी जल स्तर बहुत

कम है। मुख्य नहर में कम पानी होने और आउटलेट पर मिट्टी जमा होने के कारण पानी छोटी नहर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। मानसून और नहर से पानी मिलने में हो रही देरी के कारण किसान पहले ही अपनी फसल की बुआई व रोपाई को लेकर काफी पिछड़ चुके हैं। अब पानी के लिए की जा रही यह लंबी प्रतीक्षा उनके सब्र की परीक्षा ले रही है जिससे क्षेत्र के कृषकों में आक्रोश पनप रहा है। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की हैं की मुख्य नहर और उससे जुड़ने वाली छोटी नहर की गहराई से साफ सफाई कर भीतर जमा मिट्टी और गाद को बाहर निकाला जल प्रवाह को सुगम बनाने के लिए नहर का ढलान व्यवस्थित किया जाए ताकि पानी सुचारू रूप से खेतों तक पहुँच सके। यदि जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसानों की फसलें और अधिक प्रभावित होंगी।

नहर से नही मिल रहा किसानों को पानी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है-रंजीत बागडे

ग्रामीण रंजीत बागड़े ने बताया की गांव में जो छोटी नहर किसानों के खेतों के लिए आती है उसकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। मुख्य नहर से आधे रास्ते तक लाइनिंग कार्य किया गया था जो अभी देखने में नहीं मिल रहा है उसके ऊपर गंदगी और बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो गई है। व्यवस्थित रूप से साफ सफाई नहर की नहीं की गई है जिस कारण आखिरी तक या पानी नहीं जाता है। अभी नहर में पानी है परंतु वह छोटी नहर में नहीं निकल रहा है इस नहर की बहुत समस्या है। जिस पर सिंचाई विभाग ध्यान नहीं देता है कई बार अधिकारियों को बोला गया है लिखित शिकायत भी करें पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि उनके द्वारा सुधार किया जाना चाहिए।

कई वर्षो से नहर की जर्जर स्थिति से किसान परेशान है-पियूष शेंडे

ग्रामीण पियूष शेंडे ने बताया कि करीब ४ वर्षों से अधिक का समय हो गया है नहर की स्थिति हर बार खराब होती जा रही है। यह बहुत चौड़ी नहर थी जो अब मिट्टी एवं गाद जमा होकर आकार में सकरी होती जा रही है। नहर के अधिकारी जो आते हैं उन्हें शिकायत भी की गई है विभाग में जाकर भी चर्चा की गई है पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हर बार यही स्थिति बनी रहती है अभी जब पानी नहीं पहुंचेगा तो किसानों को नहर में मेहनत करनी पड़ेगी।

किसानों को नही मिल रहा नहर का पर्याप्त पानी-मुकेश समनपुरे

मुकेश समनपुरे ने बताया कि हमारे गांव से ही मुख्य नहर गई हुई है जिसमें करीब अभी ढाई फीट पानी बह रहा है। परंतु वह पानी कुलापे से निकल नहीं रहा है जिससे पूरी नहर सूखी हुई है। किसान पहले ही लेट हो चुके हैं अभी रोपाई के लिए पानी की आवश्यकता है किसान नहर का इंतजार कर रहा है। नहर में जलस्तर को बढ़ाना चाहिए और यह जो जमा मिट्टी है इसे निकालकर व्यवस्थित नहर बनानी चाहिए ताकि हर खेत में पानी जा सके। किसानों को और परेशान ना होना पड़े परंतु अभी तक कोई अधिकारी ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है जो चिंता का विषय है।

शैक्षणिक सत्र शुरू पर अब तक नहीं बटी विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस

आर्थिक बोझ और असमंजस में चिंतित अभिभावक

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी के अंतर्गत आने वाली शासकीय

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए काफी समय बीत चुका है। लेकिन विद्यार्थियों को मिलने वाली नि:शुल्क स्कूल ड्रेस को लेकर आज भी स्थिति पूरी तरह अस्पष्ट बनी हुई है। ड्रेस कब तक प्राप्त होगी इसे लेकर ना तो कोई दिशा निर्देश स्पष्ट हैं और ना ही शाला स्तर पर कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध है। ऐसे में विद्यार्थी और उनके अभिभावक लगातार स्कूल ड्रेस का इंतजार करने को मजबूर हैं।

पिछले वर्ष खाते में आती थी राशि, इस बार व्यवस्था में बदलाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत वर्षों तक शासन के द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खातों में ६०० रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती थी। जिससे अभिभावक स्वयं दो जोड़ी ड्रेस खरीद लेते थे। परंतु इस बार ना तो नए प्रवेशी विद्यार्थियों के खातों की जानकारी मांगी गई है और ना ही पुराने अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक विवरण अपडेट किए गए हैं। इस बार शासन के माध्यम से सीधे गणवेश उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। किंतु सत्र शुरू होने के बाद भी ड्रेस वितरण की प्रक्रिया धरातल पर शुरू नहीं हो पाई है।

विकासखंड में ८७९८ पात्र विद्यार्थी कर रहे इंतजार

वारासिवनी विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला की संख्या १४८ शासकीय माध्यमिक शाला की संख्या ७० हैं जो एकीकृत शाला की संख्या १६७ है। इसमें कक्षा १ से ५वीं तक ४५७० विद्यार्थी कक्षा ६ठवीं से८ वीं तक ४२२८ विद्यार्थी दर्ज हैं । इस प्रकार कुल पात्र विद्यार्थी की संख्या ८७९८ हैं इन सभी ८७९८ विद्यार्थियों को इस योजना के तहत नि:शुल्क यूनिफॉर्म मिलनी है जो फिलहाल केवल इंतजार के सहारे हैं।

खुशी के बीच पालकों पर बढ़ा आर्थिक दबाव

योजना के तहत नई ड्रेस मिलने की बात से विद्यार्थियों और पालकों में खुशी तो है लेकिन वितरण में हो रही देरी ने चिंता बढ़ा दी है। कई बच्चों की पिछले वर्ष की ड्रेस या तो छोटी हो चुकी है, फट गई है या खराब हो गई है। ऐसे में अभिभावक इस असमंजस में हैं कि वे बाजार से नई ड्रेस सिलवा लाये या शासन से मिलने वाली गणवेश का इंतजार करें। यदि वे खुद से ड्रेस खरीदते हैं तो उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बिना गणवेश के बच्चों को स्कूल भेजने में भी झिझक महसूस हो रही है। पालकों की मांग है कि शिक्षा विभाग और संबंधित प्रशासन इस विषय पर जल्द स्थिति स्पष्ट करें और शीघ्र अति शीघ्र गणवेश का वितरण सुनिश्चित कराए । ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और परिवारों को अनावश्यक आर्थिक परेशानी ना उठानी पड़े।

गणवेश या रुपये क्या दिये जायेंगे अभी कुछ स्पष्ट नहीं है-सत्येंद्र शरणागत

बीआरसी सत्येंद्र शरणागत ने बताया कि पिछले वर्ष तक बच्चों के खातों में ६०० रूपये दो गणवेश खरीदने डाले जाते थे परंतु इस वर्ष जानकारी है कि पैसे की जगह गणेश देंगे। परंतु स्पष्ट जानकारी कुछ भी नहीं है कि पैसे देंगे या गणेश अधिकारियों से चर्चा हुई है पर स्पष्ट नहीं है, राशि प्रवेश के दो तीन महीने में डाल जाती है या कोई विद्यार्थी के खाते में समस्या रहती है तो उसे अपडेट करवाते है। परंतु उसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है बच्चों का खाता जोड़ना प्रक्रिया में रहता है।

स्विमिंग पूल निर्माण कार्य का पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया निरीक्षण

स्विमिंग पूल में आधुनिक सुविधा मुहैया कराने दिये निर्देश

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर पालिका परिषद के द्वारा निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का बुधवार को पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने मिनी ओलपिंक की तर्ज पर होने वाले इस कार्य के संबध में निर्देश देते हुये कहा की स्विमिंग पूल में सुरक्षा, स्वच्छता और बच्चो के तैराकी सिखने जैसी बुनियादी व आधुनिक सुविधायें मिलनी चाहिये। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया की ९७ लाख रूपये की लागत से १३ मीटर बाय २५ मीटर के इस स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य सतत निगरानी में कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी इस पूल में क्षमता अनुसार साढे तीन लाख लीटर पानी भरकर इसके लिकेज व डेमेज को चेक किया जा चुका है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत सामने नही आयी है। इस पूल का निर्माण कार्य भोपाल के विशेषज्ञो के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। इसी दौरान सुनील पारधी ने जानकारी देते हुये बताया की पूल के निचले हिस्से में क्वालिटी वाली मोजेक टाईल्स लगवायी जा रही है। पूल में चेंजिंग रूम सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध रहेगी। बाबी परिहार ने बताया की इस पूल में बच्चो को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस पूल में अंडर वाटर रोशनीयुक्त लाईट के अलावा बाहर की नाली में बेहद मजबूत हाईवर ग्रिल और बाहर से फाईबर सीट से पूल को कवर्ड भी किया जा रहा है। सबसे पहले पूल के पानी को बाहर कर अब बेहद क्वालिटी वाली मोजेक टाईल्स को लगाया जा रहा है। इस पूल की यह भी विशेषता है की पूल के शुरूवाती हिस्से सात मीटर को प्लने व बाकी के १८ मीटर के हिस्से में स्लोब नजर आयेगा।

बेटी को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली कलयुगी मां को ७ साल का सश्रम कारावास

पद्मेश न्यूज।वारासिवनी। मां और बेटी के रिश्ते को तार तार कर देने वाले एक अत्यंत गंभीर मामले में वारासिवनी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर की अदालत ने अपनी ही १९ वर्षीय बेटी पर अनैतिक कार्यों गलत काम के लिए दबाव बनाने वाली कलयुगी मां को दोषी करार देते हुए ७ वर्ष के सश्रम कारावास और १००० रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह हैं पूरा मामला

सहायक लोक अभियोजक संतोष लिल्हारे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता स्व.लोकेश श्रोत्रिया की अचानक मौत हो गई थी। पिता के निधन के बाद परिजनों और रिश्तेदारों की समझाइश पर १९ वर्षीय बेटी अपनी मां प्रगति पति स्व.लोकेश श्रोत्रिया के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। दोनों थाना तिरोड़ी क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर रहे थे। मां के साथ रहने के दौरान बेटी ने देखा कि उसकी मां शराब पीने की आदी हो चुकी थी और घर में कई अनजान और संदिग्ध लोगों का आना जाना था। आरोप के मुताबिक मां अपनी ही बेटी पर घर आने वाले लोगों के साथ सोने और गलत काम करने का लगातार मानसिक व

शारीरिक दबाव बनाती थी। इसी बीच आरोपी मां ने हरिनारायण नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसके बाद मां और हरिनारायण दोनों मिलकर लड़की पर अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए दबाव बनाने लगे।

इंदौर पहुंचकर बुआ को बताई आपबीती,दर्ज हुआ मामला

मां और सौतेले पिता के प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता किसी तरह इंदौर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंची और वहां पूरी आपबीती विस्तार से बताई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुआ ने तुरंत पीड़िता को साथ ले जाकर इंदौर के लसूरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना १ जनवरी २०२१ से १ सितंबर २०२१ के बीच घटित होती रही थी जिसके बाद १६ सितंबर २०२१ को इंदौर में मामला दर्ज किया गया। चूंकि मामला थाना तिरोड़ी क्षेत्र का था इसलिए इंदौर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला आगे की कार्रवाई के लिए थाना तिरोड़ी स्थानांतरित कर दिया। तिरोड़ी पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा ३७२ एवं ५११ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और जांच पूरी कर अभियोग पत्र वारासिवनी न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय ने दी सख्त सजा

मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष सहायक लोक अभियोजक संतोष लिल्हारे की ओर से अदालत के समक्ष ८ महत्वपूर्ण गवाहों साक्ष्यों के बयान दर्ज कराए गए और २२ दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर की अदालत ने २२ जुलाई को आरोपी मां प्रगति को धारा ३६६ क के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी प्रगति को ७ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १००० रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस घिनौने अपराध में शामिल दूसरा आरोपी हरिनारायण विचारधीन अपराध के दौरान से फरार हैं । न्यायालय के द्वारा उसे भी आरोपी बनाया गया है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है।

कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल में नशे से दूरी है जरूरी २.०जन जागरूकता अभियान प्रारंभ

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल में शासन के निर्देशानुसार नशे से दूरी है जरूरी २.० जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के प्रथम दिवस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवक एवं स्वयं सेविकाओं मयूर पारधी, वैशाली पथिक, मासूम बंसोड़, मानसी हेड़ाऊ एवं अनन्या डेकाटे के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए नशे से दूरी बनाये रखते हुए नशा मुक्त भारत देश बनाने का आग्रह किया गया। एवं शासन से नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की गई। इस दिशा में तमिलनाडू एवं राजस्थान सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा भी की गई। स्कूल संचालक प्राचार्य निरंजन बिसेन के द्वारा अभियान की गतिविधियों की जानकारी आयोजित सभा में दी गई। तथा पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा भी सभा को उद्बोधित किया गया। सभा का सफल संचालन एवं आभार व्यक्त राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियान में रांगोली, चित्रकला, निबंध सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा तथा जागरूकता रैली भी निकाली जायेगी। सभा में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों एवं स्वंय सेविकाओं के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकायें अन्य कर्मचारी एवं छात्र छात्राऐं उपस्थित रही।

राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफल तीन अभ्यर्थियों को मिली 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। राज्य शासन की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के तीन अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर मृणाल मीना की स्वीकृति के बाद यह राशि संबंधित अभ्यर्थियों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर ने बताया कि किरनापुर तहसील के ग्राम चिखला की निवासी शिवानी बांगरे, वारासिवनी तहसील के ग्राम वारा की रचना बोरकर तथा गटापायली निवासी करूणा गजभिये ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि शासन की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

शिक्षा व्यवस्था पर संकट- सरकार आखिरकार शिक्षामंत्री का इस्तीफ़ा क्यों नहीं लेती?

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी युवा पीढ़ी होती है। यही युवा देश के भविष्य की नींव रखते हैं। यदि उनके सपनों, परिश्रम और भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगे तो यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। पिछले कुछ समय से देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने करोड़ों विद्यार्थियों के विश्वास को गहरी ठेस पहुंचाई है। आज लाखों छात्र यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि उनकी मेहनत का मूल्य ही सुरक्षित नहीं है, तो उनके वर्षों के संघर्ष का क्या अर्थ रह जाता है? सरकार जब किसी परीक्षा के सफल आयोजन, नई शिक्षा नीति या शिक्षा क्षेत्र में सुधार का श्रेय लेने में पीछे नहीं रहती, तब परीक्षा प्रणाली की विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी उसे स्वीकार करनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती; असफलताओं की जिम्मेदारी लेना भी सुशासन का अनिवार्य सिद्धांत है। देश के विभिन्न हिस्सों में बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं केवल तकनीकी त्रुटियां नहीं हैं। यह संकेत हैं कि परीक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं गंभीर संस्थागत कमजोरी मौजूद है। हर बार जांच समिति बनती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। इस चक्र ने विद्यार्थियों का भरोसा कमजोर किया है। आज देश का छात्र अपने अधिकारों की मांग लेकर सड़कों पर उतरने को विवश है। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर सहित अनेक स्थानों पर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लाठीचार्ज, गर्मी, बारिश और कठिन परिस्थितियों के बीच केवल एक मांग कर रहे हैं—उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा की जाए। यह विडंबना है कि जिस युवा शक्ति को पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में होना चाहिए, वह अपने अधिकारों के लिए धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार देता है। छात्रों की आवाज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनके दर्द को समझना आवश्यक है। आखिर वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि केवल निष्पक्ष परीक्षा और समान अवसर चाहते हैं। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या शिक्षा मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? भारतीय लोकतंत्र में अनेक अवसरों पर मंत्रियों ने नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर जवाबदेही की परंपरा स्थापित की है। इस्तीफा किसी व्यक्ति की हार नहीं होता, बल्कि व्यवस्था के प्रति जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान का प्रतीक भी हो सकता है। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि केवल किसी मंत्री का इस्तीफा समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यदि पूरी परीक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर नहीं किया गया, तो नया मंत्री आने के बाद भी वही समस्याएं दोहराई जा सकती हैं। इसलिए आवश्यकता व्यापक सुधारों की है—परीक्षा संचालन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित डिजिटल प्रणाली, दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई, परीक्षा माफिया पर प्रभावी नियंत्रण तथा पारदर्शी जांच व्यवस्था की स्थापना। सरकार को यह भी समझना होगा कि आज की पीढ़ी केवल आश्वासन नहीं, बल्कि परिणाम चाहती है। जेन-ज़ी कही जाने वाली यह पीढ़ी तकनीकी रूप से जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जवाबदेही की अपेक्षा रखती है।

संसद का मानसून सत्र 2026 शुरू-विपक्ष का हंगामा शुरू

- क्या अगले 25 दिन भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और विज़न- 2047 की दिशा तय करेंगे? -समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ 13 अगस्त तक चलने वाले इस संसद के मानसून सत्र पर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई है।कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं।संसद में 28 विधेयक लंबित हैं।इनमें से 5 नए विधेयक पेश किए जाने हैं और 2 लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।यह केवल एक नियमित संसदीय सत्र नहीं,बल्कि भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था निवेश वातावरण और वैश्विक छवि के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। यह सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है जब भारत दुनियाँ की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है,भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है,अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की निगाह भारत पर है और विकसित भारत -2047 का रोडमैप निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। मैं एडवोकेट किशन षणमुख दास भावना ने गोंदिया महाराष्ट्र अपने विचार इस आर्टिकल के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं कि ऐसे समय संसद में होने वाली प्रत्येक बहस, प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक राजनीतिक टकराव का प्रभाव केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि वैश्विक निवेशकों,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई देगा।सत्र प्रारंभ होने से पहले माननीय पीएम ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद का उत्पादक संचालन देशहित,जनकल्याण और विकास के लिए आवश्यक है तथा भारत की हाल की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष पहले से ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाकर आया था, जिससे पहले दिन से ही टकराव की स्थिति बन गई। साथियों, सरकार ने इस मानसून सत्र के लिए लगभग आठ प्रमुख विधेयकों का विधायी एजेंडा रखा है। इनमें इन्कम-टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल,2026,जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कर छूट से संबंधित प्रावधान।माइक्रो , स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेन्डमेंट) बिल 2026 एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था मजबूत करना।मध्यस्थता (आरबिंस्ट्रेशन) के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रावधान।राज्यों को फेसिलिटेशन कौंसिल के गठन में अधिक अधिकार देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थस एंड डेथस (अमेन्डमेंट) बिल ,2026जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के नियमों को अधिक कठोर बनाना। पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना।सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेस) अमेन्डमेंट बिल, 2026 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव। प्रेवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर (अमेन्डमेंट) बिल, 2026राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 में संशोधन। रिपोर्टों के अनुसार इसमें वंदे मातरम् को वैधानिक संरक्षण देने और उसके अपमान को दंडनीय बनाने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावापहले से लंबित प्रमुख कई विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक गलियारों में परिसीमन (डेलिमिटेशन) से जुड़े संभावित विधेयक पर भी व्यापक चर्चा रही,क्योंकि इसका संबंध भविष्य में महिलाओं के आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सरकार ने परिसीमन पर अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया,फिर भी यह विषय पूरे सत्र का सटीकता से सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन गया। साथियों,उधर विपक्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह सरकार को केवल विधेयकों पर नहीं,बल्कि महंगाई, बेरोजगारी,कृषि संकट, मणिपुर की स्थिति,नीट परीक्षा विवाद,छात्र आंदोलनों अयोध्या मंदिर दान प्रकरण तथा परिसीमन जैसे विषयों पर घेरेगा। विपक्ष का तर्क था कि जनता से जुड़े इन प्रश्नों पर पहले चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार का जोर विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने पर था। यही टकराव पहले दिन काम काज शुरू होने के पहले घंटे से ही सदन के भीतर खुलकर दिखाई दिया। 20 जुलाई की सुबह जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई,विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने छात्र आंदोलनों और परीक्षा संबंधी मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की।अध्यक्ष द्वारा बार-बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई,किंतु शोर- शराबा जारी रहा। परिणामस्वरूप दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। समाचारों के अनुसार दोपहर तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कम से कम पाँच बार स्थगित हुई और बाद में दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन कोई बड़ा विधायी कार्य नहीं हो सका। साथियों, पहले दिन की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी 25 दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों,कर प्रणाली, उद्योग,निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराना है, जबकि विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने की रणनीति अपनाए हुए है। यदि दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित नहीं होता, तो संसदीय उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।आर्थिक दृष्टि से यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशक केवल आर्थिक आंकड़े ही नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि किसी देश की संसद कितनी स्थिरता और दक्षता से निर्णय लेने में सक्षम है। यदि महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक समय पर पारित होते हैं, तो इससे भारत की निवेश क्षमता और वैश्विक विश्वसनीयता मजबूत होगी। इसके विपरीत लगातार गतिरोध से निवेशकों में अनिश्चितता का संदेश जा सकता है। साथियों, भारतीय शेयर बाजार भी इस सत्र पर निकट दृष्टि रखे हुए है। बैंकिंग, कर सुधार, एमएसएमई विनिर्माण डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े विधेयकों का सीधा प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों पर पड़ सकता है। यदि सरकार सुधारवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो दीर्घकाल में निवेशकों का विश्वास और मजबूत हो सकता है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भारत आज भी जी-20 ब्रिक्स क्वाड तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में संसद की कार्यक्षमता यह संदेश देती है कि भारत केवल तेज़ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के साथ भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए विदेशी सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और वैश्विक रेटिंग एजेंसियाँ भी इस सत्र के परिणामों पर नज़र रख रही हैं। साथियों, विजन-2047 के संदर्भ में भी यह मानसून सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है।विकसित भारत का लक्ष्य केवलआर्थिक वृद्धि से प्राप्त नहीं होगा; इसके लिए कर सुधार, औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन, शिक्षा, कृषि, डिजिटल प्रशासन और राजनीतिक सहमति जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर सुधार आवश्यक हैं। संसद इन सभी सुधारों का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। इसलिए अगले कुछ सप्ताहों में लिए जाने वाले निर्णय दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। 20 जुलाई 2026 को शाम लगभग 5 बजे तक की स्थिति यह रही कि सदन का पहला दिन राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इच्छा दोहराई, जबकि विपक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह जनहित और राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बिना सदन को सामान्य रूप से चलने नहीं देगा। साथियों, यदि भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख लोकतांत्रिकव्यवस्थाओं में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि आर्थिक विश्वास का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। अमेरिका में कांग्रेस केगतिरोध ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की राजनीतिक अस्थिरता, फ्रांस में संसद में बहुमत के संकट अथवा जापान में नीति निर्माण में देरी का सीधा प्रभाव वहां के शेयर बाजारों, विदेशी निवेश तथा मुद्रा बाजार पर पड़ता रहा है। भारत भी अब पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर एक वैश्विक शक्ति है, इसलिए भारतीय संसद की कार्यवाही पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, वैश्विक निवेश बैंक, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ निरंतर निगाह रखती हैं। यदि संसद में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों,कर प्रणालीऔद्योगिक विकास, डिजिटल गवर्नेंस, रोजगार सृजन, कृषि आधुनिकीकरण तथा न्यायिक सुधारों से जुड़े विधेयकों पर सार्थक चर्चा होती है और समयबद्ध निर्णय लिए जाते हैं, तो भारत की ईजी ऑ ? डूइंग बि ?नेस,निवेश आकर्षण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को नई गति मिल सकती है। इसके विपरीत यदि पूरा सत्र केवल राजनीतिक टकराव, नारेबाजी और बार-बार स्थगन तक सीमित रह जाता है, तो इससे सुधारों की गति प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण है, फिर भी संसदीय उत्पादकता वैश्विक निवेशकों के लिए राजनीतिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक बनी रहती है। यही कारण है कि 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ यह मानसून सत्र केवल भारतीय राजनीति का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक समुदाय की दृष्टि से भी सटीकता से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों दूसरी ओर, यह मानसून सत्र भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता की भी एक बड़ी परीक्षा है।सरकार के सामने चुनौती है कि वह अपने विकास, आर्थिक सुधार और विकसित भारत 2047 के एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए, जबकि विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है कि वह जनहित से जुड़े प्रश्नों,महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा,मणिपुरपरिसीमन सामाजिक न्याय और संघीय ढाँचे पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करे। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब सत्ता और विपक्ष दोनों टकराव के बजाय तर्क, संवाद और समाधान को प्राथमिकता देते हैं। यदि आगामी 25 दिनों में संसद सार्थक बहस, उच्च स्तर की संसदीय मर्यादा और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखते हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर सहमति बनाने में सफल रहती है, तो यह न केवल भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर और मजबूत करेगा, बल्कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाकरअर्थव्यवस्था,उद्योग रोजगार, स्टार्टअप,विनिर्माण शेयर बाजार और 'विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को भी नई गति देगा। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानसून सत्र 2026 केवल एक संसदीय कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उन ऐतिहासिक निर्णयों का मंच बन सकता है जो आने वाले दो दशकों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक भूमिका की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इस प्रकार मानसून सत्र का पहला दिन यह संकेत देता है कि अगले 25 दिन केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों, निवेश वातावरण, शेयर बाजार की दिशा और विकसित भारत-2047 के रोडमैप के लिए भी निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि सरकार और विपक्ष लोकतांत्रिक संवाद तथा रचनात्मक सहयोग का मार्ग अपनाते हैं, तो यह सत्र भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों का आधार बन सकता है; अन्यथा बार-बार का गतिरोध आर्थिक सुधारों की गति को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह आज भारतीय संसद पर टिकी हुई है।

-किशन सनमुखदास भावनानी

कानून व्यवस्था को चुनौती बन रहे हैं रंगदारी गैंग

-मनोज कुमार अग्रवाल

किसी भी राज्य में यदि गिरोह बंद अपराधी संगठित गिरोह बना कर लोगों को धमकी दे कर उन पर हमले करवा कर फिरोती या रंगदारी टैक्स की जबरन वसूली करें तो ऐसे शासन को भयमुक्त लोकतंत्र कहना गलत होगा। भाजपा के सरकार में आने और लगातार अपना जनाधार बढ़ाने के पीछे एक खास वजह यह भी है कि भाजपा ने भयमुक्त समाज का सपना दिखाया लेकिन अब भाजपा के इस थीम को अपराधी चौतरफा चुनौती दे रहे हैं ऐसे में सरकार की छवि को धूमिल करने का मकसद सफल हो रहा है और सरकार की साख को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में गैंगस्टरों और उनके गुर्गों के जबरन वसूली गिरोह (रंगदारी मांगने वाले) सक्रिय हैं जो मांगी गई रकम न मिलने पर हत्या तक करने से संकोच नहीं करते।

ये गिरोह मुख्य रूप से व्यापारियों तथा आम लोगों तक को किसी न किसी बहाने निशाना बना कर ब्लैकमेल कर रहे हैं हाल ही में एक के बाद एक ऐसी दर्जनों वारदातों ने सुर्खिया बटोरी है

16 फरवरी को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में पंकज दीक्षित नामक एक डाक्टर को असामाजिक तत्वों द्वारा 15 लाख रुपए रंगदारी देने का संदेश मिलने और रंगदारी न देने पर उसके होटल तथा पूरे परिवार को समाप्त कर देने की धमकी मिलने पर पूरा परिवार दहशत में आ गया। 4 अप्रैल को खरगौन मध्य प्रदेश में एक कॉटन व्यापारी के घर पर अंधाधुंध गोलीबारी करके लारेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और मांग पूरी न करने पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया।

18 मई को बोकारो (झारखंड) में रंगदारी की मांग के चलते जयराम प्रसाद नामक व्यक्ति की कुछ लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी।

29 मई को गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में होटल कारोबारी आलोक राय द्वारा रंगदारी देने से इन्कार करने पर स्थानीय कटरा गैंग के सदस्यों ने उनके बेटे विनीत राय की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में एनकाऊंटर में उक्त कांड के मुख्य आरोपी कमलेश को मार गिराया।

2 जून को मुंगेर (बिहार) में अपराधियों ने रंगदारी न देने पर खेत में सो रहे किसान मंसूरी यादव की गोली मार कर हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व उक्त बदमाशों ने मंसूरी यादव से रंगदारी की मांग की थी और न देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी।

3 जून को गुरुग्राम पुलिस ने रंगदारी के लिए लोगों का अपहरण करने वाले नितिन को एनकाऊंटर में घायल करके गिरफ्तार किया।

17 जून को पानीपत (हरियाणा) से एक 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण करके 1.5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के सिलसिले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को रोहतक से गिरफ्तार करने के साथ ही बच्चे को भी उनके कब्जे से छुड़ाया।

26 जून को असंध (हरियाणा) में एक मिष्ठान भंडार के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने तथा मांग पूरी न करने पर गोली मारने की धमकी देने के सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया। 29 जून को साकची (जमशेदपुर, झारखंड) में एक युवक ने एक दुकानदार द्वारा रंगदारी देने से इंकार करने पर चाकुओं से वार करके उसे घायल कर दिया।

10 जुलाई को जालंधर (पंजाब) में एक फायनेंसर को रास्ते में रोक कर और हथियार दिखा कर उससे फिरौती मांगने तथा विदेश के नम्बरों से फोन करवा कर उससे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया।

12 जुलाई को जालंधर (पंजाब) स्थित कर्मा फैशन स्टूडियो के मालिक को विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल ने 50 लाख रुपए फिरौती देने का संदेश भेजा और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी।12 जुलाई को ही दिल्ली पुलिस ने एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में विदेश में मौजूद गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के 3 शूटरों शिव गोविंद, अभिनव उर्फ आकाश तथा विवेक को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 3 अत्याधुनिक पिस्तौल, 26 कारतूस तथा मोबाइल फोन बरामद किए।

पता हो कि भारत में रंगदारी और डिजिटल जबरन वसूली संगठित अपराध का एक बड़ा और गंभीर नेटवर्क बनता जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के आने से अपराधियों ने अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों को अपना धंधा बना लिया है।रंगदारी के बदलते तरीकेडिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी- अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताकर लोगों को ऑनलाइन डराते हैं। वे पीड़ितों को घंटों वीडियो कॉल पर बंधक जैसी स्थिति में रखकर लाखों रुपये वसूलते हैं। फर्जी लोन ऐप्स लोगों को छोटा कर्ज देते हैं। बाद में उनके फोन का डेटा हैक कर, अश्लील तस्वीरें बनाकर और परिवार को बदनाम करने की धमकी देकर जबरन वसूली करते हैं।

इंटरनेशनल गैंग्स और वर्चुअल नंबर्स- लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े संगठित गैंग विदेशों (जैसे कनाडा, दुबई) में बैठकर वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर्स से व्यापारियों और मशहूर हस्तियों को धमकी भरे कॉल करते हैं। पुलिस से बचने के लिए अब रंगदारी की रकम कैश के बजाय बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी में मांगी जाती है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता है।सरकार और प्रशासन के कदम नेशनल साइबर क्राइम सरकार ने cybercrime.gov.in पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, जहां तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है।गैंगस्टर्स पर सख्त कार्रवाई- राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्यों की पुलिस (जैसे मकोका या एंटी-एक्सटॉर्शन सेल) इन गिरोहों के वित्तीय नेटवर्क और संपत्तियों को कुर्क कर रही है।जागरूकता अभियान- बैंकों और गृह मंत्रालय द्वारा लगातार लोगों को अनजान कॉल्स और ऐप्स से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है।

इस प्रकार की घटनाओं के विषय में पुलिस का कहना है कि वसूली की काल आने के बाद बिचौलिए भी समझौता करवाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और इनमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के कारण लोगों में दहशत व्याप्त है। अतः ऐसे गिरोहों को सख्ती पूर्वक फौलादी हाथों से कुचलने की आवश्यकता है ताकि लोग निर्भीकतापूर्वक अपना कारोबार कर सकें और निश्चित होकर जी सकें।

मिशन पंजाब की शुरुआत

पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब पंजाब को अपने अगले बड़े राजनीतिक लक्ष्य के रूप में सामने रखना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से मिशन पंजाब का औपचारिक आगाज किया। हरियाणा के जींद और चंडीगढ़ से होते हुए जालंधर पहुंचे प्रधानमंत्री ने 5470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि पंजाब के समग्र विकास के लिए राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा संबोधन केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसमें आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीतिक रणनीति भी स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने किसानों, दलितों, युवाओं, व्यापारियों और उद्योग जगत को केंद्र में रखकर भाजपा की भावी राजनीति की दिशा तय करने का प्रयास किया। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि पंजाब को राजनीतिक अस्थिरता और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकालकर विकास की मुख्यधारा में लाने का काम केवल भाजपा कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी पंजाब के साथ भेदभाव नहीं किया। राज्य में भाजपा की सरकार न होने के बावजूद केंद्र ने विकास कार्यों के लिए लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि यदि राज्य और केंद्र दोनों में एक ही विचारधारा की सरकार होगी तो विकास की गति कई गुना तेज होगी और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब देश का अन्न भंडार है और यहां के किसानों ने हमेशा राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि किसानों को मूल्य संवर्धन, भंडारण और निर्यात से भी जोड़ना होगा ताकि उनकी आमदनी में वास्तविक वृद्धि हो सके। दलित समाज का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब सामाजिक न्याय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा, स्वरोजगार, आवास, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती है तथा किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करती। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला समय नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और आधुनिक उद्योगों का है। पंजाब के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें बेहतर अवसर और सही वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। उनका कहना था कि पंजाब के युवाओं को नशे और निराशा से बाहर निकालकर रोजगार और विकास के रास्ते पर लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यापारियों और उद्योग जगत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब को एक बार फिर औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से निवेश बढ़ेगा और नए उद्योग स्थापित होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वयं को कट्टर ईमानदार बताते थे, वे आज कट्टर बेईमान साबित हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, झूठे वादे और प्रशासनिक विफलताओं ने पंजाब की जनता का भरोसा तोड़ा है। उनके अनुसार राज्य सरकार विकास की बजाय राजनीतिक प्रचार में अधिक व्यस्त है और जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पार्टी लगातार आंतरिक कलह से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का अधिक समय आपसी संघर्ष में बीतता है जबकि जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। उनके अनुसार जिस दल में नेतृत्व को लेकर निरंतर विवाद हो, वह राज्य को स्थिर और प्रभावी शासन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो निर्णय लेने में सक्षम हो और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि देश और राज्यों के दीर्घकालिक विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले वर्षों में भी विकास की यह गति और तेज होगी। जालंधर की जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक नया इतिहास भी रचा। जींद से सोनीपत के बीच शुरू हुई इस ट्रेन को भारत के हरित परिवहन अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद, सोनीपत और पूरा हरियाणा इतिहास का हिस्सा बन गया है क्योंकि देश ने स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि 2014 से पहले पश्चिम एशिया जैसा बड़ा संकट आता तो भारत की रेलवे व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती क्योंकि उस समय अधिकांश रेल सेवाएं डीजल पर निर्भर थीं। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लगभग 99 प्रतिशत रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम हुई है और रेलवे अधिक आधुनिक, सुरक्षित तथा पर्यावरण के अनुकूल बनी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब केवल पारंपरिक विकास मॉडल तक सीमित नहीं है बल्कि हरित ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के नए युग में प्रवेश कर चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत रेलवे, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की जालंधर रैली केवल विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों का स्पष्ट संकेत भी थी। किसानों, दलितों, युवाओं, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर भाजपा ने अपने चुनावी अभियान की रूपरेखा सामने रख दी है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप और कांग्रेस पर आंतरिक कलह का हमला भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके माध्यम से वह स्वयं को स्थिर, निर्णायक और विकासोन्मुख विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की यह रणनीति पंजाब की राजनीति में कितना प्रभाव डालती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से मिशन पंजाब की शुरुआत करते हुए राज्य की राजनीति में चुनावी माहौल को नई दिशा दे दी है और भाजपा ने यह संकेत भी दे दिया है कि अब उसका लक्ष्य केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं बल्कि पंजाब में सत्ता तक पहुंचना है।

-कांतिलाल मांडोत

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। बुधवार को पूछपरख के बीच दलहनों में चना बाजार तेजी पर रहे। तुअर व उड़द में टिकाव रहा। खाद्य तेलों में बाजार मजबूत बने रहे। तिलहनों में सोयाबीन 100 रू. क्विंटल की घटत पर रहा। किराना जिंसों में शक्कर सुर्ख रही। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार चने में पूछपरख के बाद भावों में तेजी देखी गयी। उड़द व तुअर में टिकाव देखा गया। खाद्य तेलों में व्यापार सामान्य रहा। तिलहनों में सोयाबीन 100 रू. प्रति क्विंटल की टूटत पर रहा। उधर, किराना जिंसों में शक्कर बाजार मजबूत बने रहे। खोपरा गोला व नारियल बाजार बढ़त बनाये रहे। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4750-4850, खोपरा गोला 375-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडि?यम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2500, (160) 2900, (200) 3100, (250) 3600,

तेल- सींगदाना 1750-1770, मुम्बई 1745, राजकोट तेलिया 2700, सोया साल्वेंट 1415-1420, सोया रिफाइंड 1475-1480, कपास्या 1600, धूलिया 1590-1600, कड़ी 1600,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1700, मुम्बई पाम 1500, मुम्बई सोया 1520,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2660, देवास-उज्जैन 2660, खंडवा-बुरहानपुर 2635, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8100-8400, रायडा 7000-7200, सोयाबीन 7100, टोली (महुआ बीज) 5300-5400, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6450-6500, एवरेज 6100-6200, विशाल 6250-6300, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000-6050, एवरेज 5800-5900, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7250, मूंग पुराना बोल्ड 7600-7900, मीडियम 7400-7700, मोगर 5500-6500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9500-9700, उड़द गर्मी 8800-9500, ग्रेविटी क्लीन 10100-10200, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। विश्व बाजार में चल रही अस्थिरता के चलते बुधवार को स्थानीय सराफा बाजार में दोनों मूल्यवान धातुओं में बाजार तेजी के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चॉंदी (9999) 224000, चॉंदी (99) 223900, टंच 223200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 142000,

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ ही 96.54 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया 96.34 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं गत दिवस ये 96.27 पर बंद हुआ था। कच्चे तेज की कीमतों में आई तेजी से भी रुपये पर दबाव आया है। । वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने से भी एशिया की अधिकतर मुद्राओं की तरह रुपया भी दबाव में रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करने से अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी जिससे भी रुपये पर दबाव बना।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आयी है। इसके अलावा अमेरिका के आयातित जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की योजना से भी बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे दवा कंपनियों के शेयरों में खासी गिरावट आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 715.06 अंक टूटकर 76,755.05 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 191.45 अंक नीचे आकर 23,996.25 अंक पर बंद हुआ। आज बाजार में आई गिरावट से बाजार पूंजीकरण 4 लाख करोड़ रुपये नीचे आकर र 480 लाख करोड़ रुपये ही रह गया। जिससे भी निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट रही। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा के शेयर गिरे। वहीं

दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावरग्रिड, एनटीपीसी, टाइटन, एशियन पेंट्स, आईटीसी के शेयरों में तेजी रही। आज दवा कंपनियों के शेयरों तें जबरदस्त गिरावट आई। सन फार्मा का शेयर 0.98 फीसदी गिरावट के साथ 1942.95 रुपये पर बंद हुआ। डॉ रेड्डीज लैब का शेयर 1.95 फीसदी गिरकर 1183 रुपये पर बंद हुआ। अरबिंदो फार्मा का शेयर भी 1.99 फीसदी नीचे 1549 रुपये पर बंद हुआ। निफ्टी में इंडिगो, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप में भी गिरावट दर्ज की गयी। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट आई। वहीं, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं इससे पहले आज सुबह भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सुबह 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 388 अंक की गिरावट के साथ 77,081 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी गिरावट के साथ ही 24,100 अंक के आसपास बना रहा।

एआई नियम अब और होंगे सख्त! डेटा अधिकार में बड़े बदलाव पर विचार कर रही सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी। केंद्र सरकार आईटी एक्ट, 2000 और इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस की समीक्षा कर रही है ताकि इनमें कमियों की पहचान की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इन कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तावित नए एआई कानून में जरूरी प्रावधान किए जाएंगे, जिस पर सरकार काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम मुद्दों में से एक यह है कि फ्रंटियर एआई मॉडल और टूल्स विकसित करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने का ढांचा कैसा हो और क्या उन्हें भी सेफ हार्बर का कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसका ढांचा कैसा होना चाहिए। अभी सामान्य समझ यह है कि ये सभी कंपनियां इंटरनेट इंटरमीडियरी की व्यापक श्रेणी में आती हैं, लेकिन केवल यह कहना कि वे सिर्फ एक टूल उपलब्ध कराती हैं और उस टूल से तैयार होने वाले कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उचित तर्क नहीं माना जा सकता। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित एआई कानून में सिंथेटिक मीडिया के रेगुलेशन, फ्रंटियर एआई मॉडल और टूल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा पर सहमति की व्यवस्था और लार्ज लैंग्वेज मॉडल व स्मॉल लैंग्वेज मॉडल द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा के मालिकाना हक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का गठन किया था। इसके अलावा एआईजीईजी के तहत टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई। टीपीईसी की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन कर रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ला रही है देश का पहला ब्लॉकचेन लैंड कानून

नई दिल्ली। एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन ऐंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन ऐसेट' (डेल्टा) अधिनियम पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस अधिनियम का मकसद अचल संपत्तियों का ब्लॉकचेन-आधारित टोकनाइजेशन करना है। टोकनाइजेशन जानकारियां सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है जिसमें संवेदनशील जानकारियां टोकन में तब्दील कर दी है। राज्य सरकार जमीन की वास्तविक क्षमता या अव्यक्त मूल्य का लाभ लेने और साल 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह में राजस्व के नए स्रोत तैयार करना चाह रही है। सोमवार को राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य ने प्रस्तावित अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की। इस अधिनियम का मकसद ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर जमीन से जुड़ी जानकारियों के डिजिटलीकरण टोकनाइजेशन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। सीएमओ की तरफ से जारी एक वक्तव्य के मुताबिक फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अचल संपत्तियों की अव्यक्त मूल्य का इस्तेमाल जनहित में करने के लिए नया कानून प्रस्तावित करें। इस समिति में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीएसई और एनएसई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और अनुभवी पेशेवर शामिल होंगे। प्रस्तावित कानून का मकसद एक पूर्ण डिजिटल ढांचा तैयार करना जिसमें अचल संपत्तियों को उनके असल मूल्य के आधार पर टोकन में बदला जा सके। इससे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिये लेन-देन हो सकेंगे जिसमें जमीन के मूल्य के आधार पर जारी किए गए टोकन के जरिए से लेन-देन होंगे। सरकार ने कहा कि इस कानूनी ढांचे का मकसद ऐसे लेन-देन को कानूनी सुरक्षा देना और जायदाद के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता लाना है। फडणवीस ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे कानून को अंतिम रूप देने से पहले परिसंपत्ति टोकेनाइजेशन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों, नियमों और काम-काज के तरीकों का अध्ययन करें।

मेष- आज का दिन आपके लिए नई खुशियां और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत लेकर आया है। मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिल सकता है। संतान की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा।

वृषभ- आज का दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे और आप अपने सहयोगियों से भी बेहतर प्रदर्शन करवाने में सफल रहेंगे। विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से संतोष का अनुभव होगा। यदि प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी।

मिथुन- आज का दिन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य को अपने काम में शामिल कर सकते हैं। वाणी पर संयम बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है।

कर्क- आज का दिन खुशियों और सुकून से भरा रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी पार्टी या पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। घर से निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के लिए प्रशंसा और सफलता मिलेगी। अपनी किसी पुरानी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई से जुड़ी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी और मन एकाग्र रहेगा।

सिंह- आज व्यस्तता जरूर रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता के करीब ले जाएगी। व्यापार में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परिणाम आपके पक्ष में आने में थोड़ा समय लग सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसरों पर आपका ध्यान रहेगा। पिताजी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मान-सम्मान और पहचान बढ़ेगी।

कन्या- आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन करेगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना समझदारी होगी। धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं और कोई पुराना लेन-देन भी समाप्त हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए उन्हें अधिक एकाग्र रहने की आवश्यकता होगी। एक साथ कई जिम्मेदारियां आने के बावजूद आप सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा।

तुला- आज का दिन आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह देता है। कानूनी या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कोई भी कदम सोच-समझकर उठाएं। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था, तो उसे निभाने का प्रयास करें। संतान की उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव कराएंगी। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें। धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

वृश्चिक- आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी और कई रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें। यदि पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, तो समय रहते उचित सलाह लें।

धनु- आज आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन घर का माहौल खुशनुमा बनाएगा। विद्यार्थियों का मन नई चीजें सीखने में लगेगा और किसी नए कोर्स की शुरुआत करने का विचार बन सकता है।

मकर- आज आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप उन्हें पार कर लेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। लंबे समय से टाले गए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं।

कुंभ- आज स्वास्थ्य के मामले में राहत महसूस होगी और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। पिताजी की सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनें। यदि किसी समस्या को लेकर मन परेशान था, तो उसका समाधान मिलने की संभावना है।

मीन- आज का दिन छोटे-छोटे अवसरों को बड़े लाभ में बदलने का रहेगा। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप अपने सभी जरूरी काम समय पर पूरे करने में सफल रहेंगे। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी, हालांकि कुछ नए विरोधी भी सामने आ सकते हैं।

शब्दजाल - 8328

शब्दजाल में दस पालतू जानवरों के नाम ढूंढिए. दिए गए दस नाम उपर से नीचे व तिरछे भी हो सकते हैं.

खरगोश,बिल्ली,कुत्ता,गाय,भैंस,ऊंट,गधा, बकरी,बंदर,घोड़ा

ग	क	ल	ड	व	ल	र्प	धी	ऊं	ल	ज
र	धा	ल	भैं	स	ति	ग्र	इं	ट	ट	वा
त	स	या	ल	बि	ल्ली	रा	रा	आ	ख	गा
ब	ज	ज	सु	पु	र	रा	प	ए	ली	य
म	क	दो	ग	त्ता	लं	स	तू	उ	झ	म
स	क	री	प	ख	न	पू	ना	फ	घ	त
त्ते	अ	स	त	र	प	न	श	ज	ला	ट
पे	ता	दा	ई	गो	ब	कु	फ	रा	श	न
बं	बा	चे	न	श	जी	ई	त्ता	ल	प	रु
द	पा	ला	ल	न	क	दु	र	शा	श्री	ता
र	रा	जी	घो	ड़ा	धी	रा	इ	फ	ई	त

शब्दजाल - 8327 का हल

[illegible]										
व	रो	ल	प	गा	आं	धी	तू	फा	न	ले
श	बा	ज	स	ने	क	छ	र	ग	श	थ
छ	त्ती	स	घं	टे	न	ज	स	शा	जू	ध
द	र	ल	म	ह	र	औ	के	स	प	र्मा
थो	बु	लं	दी	र	हो	ग	या	दु	र	त्मा

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

23 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	कर्क में	सिंह	07.19 बजे से
चंद्र	तुला में	कन्या	09.31 बजे से
मंगल	वृष में	तुला	11.42 बजे से
बुध	मिथुन में	वृश्चिक	13.57 ब.से
गुरु	कर्क में	धनु	16.13 बजे से
शुक्र	सिंह में	मकर	18.18 बजे से
शनि	मीन में	कुंभ	20.04 बजे से
राहु	कुंभ में	मीन	21.37 बजे से
केतु	सिंह में	मेष	23.08 बजे से
राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक		वृष	00.48 बजे से
		मिथुन	02.46 बजे से
		कर्क	04.59 बजे से

गुरुवार 2026 वर्ष का 204 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** आषाढ़ **पक्ष** शुक्ल **तिथि** नवमी 07.04 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** विशाखा 01.43 बजे रात्र को समाप्त। **योग** शुभ 19.20 बजे को समाप्त। **करण** कौलव 07.04 बजे तदनन्तर तैतिल 20.06 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 8.6 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 20° 07' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872779 **जूलियन दिन** 2461244.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** सफर **तारीख** 08 **विशेष** नवरात्रि समाप्त, लोकमान्य तिलक जयंती।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
शुभ	05.54 से 07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से 07.11 बजे तक
रोग	07.22 से 08.51 बजे तक	चर	07.11 से 08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से 10.19 बजे तक	रोग	08.43 से 10.15 बजे तक
चर	10.19 से 11.47 बजे तक	काल	10.15 से 11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से 01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से 01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से 02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से 02.51 बजे तक
काल	02.43 से 04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से 04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से 05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से 05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7272

1		2	3		4		5		6
		7					8		
	9								
10				11		12		13	
			14			15			
16		17			18				
19			20	21			22		23
		24				25			
	26		27		28				
29					30				

ऊपर से नीचे:-

१. नसीरूद्दीनशाह, जैकीश्रॉफ, नगमा की फिल्म-२
२. करणनाथ, मनीषा नतान्यासिंह की 'क्यूं मेरा दिल' गीत वाली फिल्म-२
३. अमिताभ, वहीदा, जीनत की फिल्म-३
४. ऋषिकपूर, श्रीदेवी की 'बदली है ना बदलेगी' गीत वाली फिल्म-४
५. देवानंद, मधुबाला की फिल्म-३
६. 'बनाकेक्यूं बिगाड़ा रे' गीत वाली फिल्म-३
९. अमिताभ, संजयदत्त, अक्षयखन्ना, अमृता राव की फिल्म-३
११. 'यारा ओ यारा' गीत वाली फिल्म-२
१२. 'खाई है रे हमने' गीत वाली राजेंद्र, शर्मिला की फिल्म-३
१३. फिल्म 'सपने साजन के' की नायिका-३
१४. राजकपूर, दिलीपकुमार, नर्गिस की 'झूम झूम के नाचो आज' गीत वाली फिल्म-३
१६. 'हैलो हैलो बोल के' गीत वाली फिल्म-३
१८. सनी देओल, सुष्मिता सेन की 'मैं अपना नाम भूला' गीत वाली फिल्म-२
२१. 'मेरे तो गिरधर गोपाल' गीत वाली फिल्म-२
२२. मनोजकुमार, साधना की फिल्म-४
२३. 'जो उनकी तमन्ना है' गीत वाली फिल्म-४
२४. राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-२
२६. 'सुना था देखा ना था' गीत वाली आफताब, उर्मिला की फिल्म-२
२७. अमिताभ, रितिक, प्रीति की फिल्म-२
२८. 'फूलों से जो खुशबू आए' गीत वाली फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. सैफअली खान, रानी मुखर्जी की 'सांसों को सांसों में ढलने दो' गीत वाली फिल्म-२,२
४. 'रंग भरे मौसम से रंग चुराके' गीत वाली जैकी श्रॉफ, जूही चावला की फिल्म-३
७. गोविंदा, मनीषा की 'ठहरो तो सही सोचो तो जरा' गीत वाली फिल्म-४
८. 'संडे की रात थी' गीत वाली गोविंदा, रवीना की फिल्म-३
१०. ऋषिकपूर, शाहरूख, दिव्या भारती की 'तेरी उम्मीद तेरा इंतजार' गीत वाली फिल्म-३
११. फिल्म 'मनोरंजन' में शम्मीकपूर के साथ नायिका कौन थी-३
१४. सलमान, सोमी की 'दिल मेरा यहां' गीत वाली फिल्म-२
१५. 'कब के बिछड़े हुए' गीत वाली अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-४
१७. अमजद खान, बिंदिया गोस्वामी की 'दिल के टुकड़े टुकड़े' गीत वाली फिल्म-२
१८. 'मेरे खयालों की मलिका' गीत वाली शाहरूख, चंद्रचूड़, ऐश्वर्या, प्रिया की फिल्म-२
१९. सुनील शेट्टी, रंभा की 'कहां गये ममता' गीत वाली फिल्म-२
२०. 'तुम भी चलो' गीत वाली अमिताभ, विनोद खन्ना, सायरा बानो की फिल्म-३
२५. अमिताभ, अरशद वारसी, करिश्मा, विजय शांति की फिल्म-४
२६. 'ये दपनियावाले' गीत वाली देवानंद, आशा पारेख की फिल्म-३
२९. धर्मेन्द्र हेमा की 'दुनिया जब' गीत वाली फिल्म-२
३०. अक्षयकुमार, सुनील शेट्टी, करिश्मा, सोनाली की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7271

[illegible]

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: संपत्ति बनाम सुख

बहुत पुरानी कथा है। एक बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था माइडाज। वह बेहद लालची था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन दिन-प्रतिदिन कुछ और पाने की उसकी ललक बढ़ती ही जाती थी। सोने के लिए उसके भीतर खास कमजोरी थी। वह दिन-रात सोने के ख्यालों में खोया रहता। वह कल्पना किया करता कि उसका विशाल घर सोने से भर जाए। उसने धन कमाने के साथ-साथ देवता की आराधना की। उसकी साधना से प्रसन्न होकर देवता ने उससे कोई वर मांगने को कहा। सोने के लालची माइडाज को और तो कुछ सूझा नहीं। उसने कहा, 'प्रभो, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं जो भी छुऊं, वह सोने का हो जाए।' देवता ने कहा, 'ऐसा ही होगा।' यह कहकर वह चले गए। माइडाज ने सबसे पहले अपने महल के खम्भे छुए। वे एकदम सोने के हो गए। फिर तो उसने एक-एक करके अपने घर की सारी चीजें छू डालीं। सब सोने की हो गईं। उसे भूख लगी। उसने खाना मंगवाया। जैसे ही उसने खाने को छुआ वह सोने का हो गया। यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। वह सोना खाकर पेट नहीं भर सकता था और भूखा रहकर जी नहीं सकता था। उसका सारा आनंद विषाद में परिणत हो गया। उसकी एक लड़की थी। वह पिता के वरदान से बड़ी खुश थी पर पिता की व्यथा से बहुत दुखी हुई। वह दौड़ी-दौड़ी पिता के पास आई। उसका पिता तो शोक-सागर में डूबा था। बेटी के सामने आते ही वह बिलखते हुए उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा लड़की सोने की हो गई। माइडाज की दुनिया लुट गई। वह समझ गया कि आदमी को धन-दौलत जीवित नहीं रखती। वह जीवित रहता है प्यार के लिए, वह जीवित रहता है सुख के लिए। लेकिन वह प्यार, वह आनंद, वह सुख धन-संपत्ति में नहीं है।

सूडोकु नवताल- 7581

★★★★★ कठिनतम

	9				4			7
					7	9		
8								
4		5	8					
3				1				2
					9	7		6
								4
		3	5					
2			6				8	

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
■ पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकु नवताल -7580 का हल

7	8	5	2	6	3	1	4	9
4	3	1	9	7	5	8	2	6
2	6	9	1	4	8	7	5	3
3	1	4	6	8	9	5	7	2
9	5	8	7	2	4	6	3	1
6	2	7	3	9	6	1	8	4
1	4	6	8	5	2	3	9	7
8	9	3	4	1	7	2	6	5
[illegible]								

शब्द पहेली - 8796

1			2	■	■	3		4
	■	■	5	6	7		■	
8	9	■	■	10		■	■	
■	11	12	■		■	13	14	
■	15			■	16			■
17			■	18	■	19		■
	■	■	20		■	■	21	22
	■	23			24	■	■	
25			■	■	26			

बाएँ से दाएँ

1. अँगरखा-4
3. मान-सम्मान,इज्जत-3
5. शुभाशीर्वाद,नियामत-4
8. केश-2
10. कसम,प्रतिज्ञा,वचन-2
11. बुरी आदत-2
13. मगरमच्छ-3
15. परिणाम-3
16. माँड़ी,स्टार्च-3
17. अक्षर (उर्दू-3)
19. रोम,केश-2
20. अधिकार,आरोप-2
21. सतह,स्तर,पटल-2
23. लूटपाट,डाका-4
25. सभ्यीकरण,विवेक-3
26. एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1. अनोखा,विचित्र,विलक्षण-3
2. नया,नवीन-2
3. इज्जत-2
4. कपोल-4
6. गमन,प्रेषित-3
7. पिता के पिता-2
9. चुनौती-4
13. गंदगी का ढ़ेर-3
14. असावधानी-4
17. जेल,कालकोठरी-4
18. शोर,ध्वनि,कंपन्न-3
20. ताप,शवदाह-2
22. यज्ञ,आहुति दान-3
23. रहस्य-2
24. जल, पानी-3

शब्द पहेली -8795 का हल

[illegible]

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

लांजी का सुभाष चौक नगर के विकास का नहीं नाकामी का दिखा रहा सबूत

पद्मेश न्यूज। लांजी।

कहते हैं किसी शहर की पहचान उसके मुख्य चौराहे से होती है, लेकिन धर्मनगरी लांजी का सबसे व्यस्ततम सुभाष चौक आज विकास का नहीं, बल्कि नगर परिषद की नाकामी, प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता का जीवित दस्तावेज बन चुका है। यह ऐसा चौक है जहां हर दिन सैकड़ों लोग जाम में फंसते हैं, नालियों की सड़ांध में सांस लेते हैं और अतिक्रमण के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। हैरानी की बात यह है कि यही रास्ता नगर परिषद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नजरों से भी रोज गुजरता है, लेकिन शायद उन्हें यह सब दिखाई नहीं देता। नगर परिषद लांजी विकास के बड़े-बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बारिश का पानी सड़कों पर बहता है, नालियां गंदगी से पटती हैं, सड़कें अतिक्रमण में सिमटती जा रही हैं और यातायात भगवान भरोसे चल रहा है। सवाल यह है कि जब नगर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे की यह हालत है, तो बाकी वार्डों का क्या हाल होगा?

सड़क नहीं दुकानें ही दुकानें

सुभाष चौक में सड़क अब सड़क कम और अस्थायी बाजार ज्यादा नजर आती है। दोनों ओर फैली दुकानें, सड़क तक पहुंच चुका अतिक्रमण और बीच रास्ते खड़े वाहन हर घंटे जाम को न्योता देते हैं। रविवार बाजार के दिन तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैदल निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं रहता। पुराने थाना परिसर के दोनों ओर के रास्ते भी धीरे-धीरे अतिक्रमण की गिरफ्त में समा चुके हैं। यदि आमने-सामने दो चारपहिया वाहन आ जाएं तो लंबा जाम लगना तय है। ऐसे में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का गुजरना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद चुनाव के समय हर गली-मोहल्ले में नजर आते हैं। लेकिन नगर की सबसे बड़ी समस्या बन चुके सुभाष चौक के अतिक्रमण, गंदगी और जाम पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जनता पूछ रही है कि क्या जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल फीता काटना और मंच साझा करना रह गया है?

सीएमओ और इंजीनियर साहबकभी पैदल भी निकलिए

नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और इंजीनियर यदि एक दिन बिना सरकारी वाहन के पैदल सुभाष चौक का निरीक्षण करें, तो उन्हें समझ आएगा कि नागरिक रोज किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। कार्यालय की फाइलों में शहर व्यवस्थित दिखाई दे सकता है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करो तो हर बार एक ही जवाब मिलता है-संज्ञान में है....,देखते हैं.....,नोटिस भेजेंगे.....,जल्द कार्रवाई होगी....., लेकिन यह जल्द आखिर किस कैलेंडर में आता है इसका जवाब आज तक किसी अधिकारी ने नहीं दिया।

नांगझिरी बालाघाट रोड से राजमार्ग तक बनेगी पक्की सड़क, 1.29 करोड़ की मिली स्वीकृति

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप नांगझिरी बालाघाट रोड से राजमार्ग तक डामरीकृत पक्की सड़क बनने के लिए पूरक बजट 2026-27 में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग के निर्माण होने से दखनीटोला आवास, साप्ताहिक बाजार एवं बिसोनी जाने वाले लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होगी और बरसात के दिनों में कीचड़ व गड्ढों से जनजीवन प्रभावित नहीं होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग लांजी — गोंदिया राजमार्ग (बाज़ार रोड) से बालाघाट रोड नांगझिरी तक तथा बालाघाट रोड से लगभग 200 मीटर आगे स्थित समशान घाट तक डामरीकरण मार्ग निर्माण के लिए किया जाएगा। यह मार्ग खासकर दखनीटोला आवास और बाजार जाने वाले ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले वर्ष बरसात में आवासटोला के निवासियों ने इसी मार्ग की बदहाली के विरोध में आंदोलन भी किया था।

बिसोनी के सरपंच प्रतिनिधि व पंचायत सदस्य विजय वारे ने बताया कि स्थानीय जनता लंबे समय से बिसोनी गुजरी चौक मार्ग को तालाब के नीचे से लांजी-गोंदिया राजमार्ग से जोड़ने की भी मांग कर रही है। विधायक राजकुमार कर्राहे ने इस मांग पर तेजी से स्टीमेट तैयार कराने के निर्देश दिए हैं और शीघ्र ही इसे भी स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है।

स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलवाने में विधायक की भूमिका की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि सड़क बन जाने से न केवल रोजमर्रा की आवागमन की समस्या हल होगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और कृषि वाहनों के परिवहन में भी आसानी आएगी।

जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए बालाघाट के वीशू मतेल का चयन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट हॉकी संघ व नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के हॉकी खिलाड़ी वीशू मतेल का जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए चयन किया गया है। ये जिले के हॉकी खिलाडियों व खेल प्रेमी दर्शकों के लिए गौरव की बात है। इस संबंध में बालाघाट हॉकी संघ के अध्यक्ष किरणभाई त्रिवेदी ने बताया कि हॉकी मध्यप्रदेश 16 वीं हॉकी इण्डिया जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2026 में प्रदेश से 18 खिलाडियों का चयन किया गया है। इसमें जिले के बालाघाट हॉकी संघ के खिलाड़ी वीशू मतेल का चयन किया गया है। उक्त प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कोयम्बटूर तमिलनाडू में आयोजित की जा रही है इसके लिए 23 जुलाई से चयनित खिलाडियों के लिए भोपाल में कोचिंग कैम्प लगाया जा रहा है। इसमें खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बालाघाट हॉकी संघ के खिलाड़ी वीशु मतेल का जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए चयन होने पर हॉकी संघ के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, रमेश रंगलानी, सचिव विजय वर्मा, उपाध्यक्ष साक्षी लिल्हारे, अभय सेठिया, ऋषभदास वैद्य, पूरनसिंह भाटिया, सुशील वर्मा, जिला खेल अधिकारी राहुल बारेसा, मकरंद अंधारे, तुषार मानकर, प्रमोद तिवारी, राधेलाल दौने, राजकुमार शांडिल्य, राजेश सेवईवार, रमेश उके, गोपाल धुर्वे, सत्यम वर्मा, आकाश लिल्हारे, सत्यम बरडे, जावेद खान सहित अन्य ने हर्ष व्यक्त कर बधाई देते हुए सफलता की कामना की है।

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ कोटवार संघ मैदान में उतरा

ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ, तहसील शाखा लांजी ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। लांजी। गांव का सबसे छोटा कर्मचारी, लेकिन जिम्मेदारियों का सबसे बड़ा बोझज् यही कोटवार की पहचान है। सीमित मानदेय में दिन-रात प्रशासन की हर सूचना और व्यवस्था का आधार बनने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन ने स्वयं सेवा अवधि बढ़ाई थी, तो अब बीच रास्ते में सेवा समाप्त करना उनके साथ न्याय नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक आघात है। यही कारण है कि वर्षों तक शासन का आदेश निभाने वाले कोटवार अब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। गांव-गांव में शासन और प्रशासन की आंख, कान और पहली कड़ी माने जाने वाले कोटवार आज खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। जिन कंधों पर वर्षों तक राजस्व, पुलिस, चुनाव, आपदा, सरकारी योजनाओं की सूचना से लेकर हर प्रशासनिक जिम्मेदारी का बोझ रहा, आज उन्हीं को एक आदेश से सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मामूली मानदेय में दिन-रात शासन की सेवा करने वाले कोटवारों के साथ हुए इस फैसले ने लांजी में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब तहसीलदार के आदेश के खिलाफ कोटवार संघ खुलकर मैदान में उतर आया है। बुधवार 22 जुलाई को मध्यप्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ, तहसील शाखा लांजी के बैनर तले बड़ी संख्या में कोटवारों ने कलेक्टर बालाघाट के नाम अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी को ज्ञापन सौंपते हुए सेवा से पृथक किए गए कोटवारों को तत्काल बहाल करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि लांजी तहसील के लगभग 15 कोटवारों को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने का हवाला देते हुए तहसीलदार द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया है। जबकि वर्ष 2023 में शासन द्वारा इन कोटवारों की सेवा अवधि में पांच वर्ष की वृद्धि करते हुए उनका एम्प्लॉय कोड भी जारी किया गया था। कोटवार संघ का कहना है कि जब शासन ने स्वयं सेवा अवधि बढ़ाई और एम्प्लॉय कोड जारी किया, तो फिर मात्र तीन वर्ष बाद ही उन्हें सेवानिवृत्त करना किस नियम और किस आधार पर उचित माना जा रहा है? संघ का आरोप है कि यह निर्णय न केवल विरोधाभासी है बल्कि कोटवारों के साथ अन्याय भी है। संघ ने यह भी दावा किया कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों और तहसीलों में जिन कोटवारों की सेवा अवधि बढ़ाई गई है, उन्हें इस प्रकार समय से पहले सेवा से पृथक नहीं किया गया। ऐसे में लांजी में लिया गया यह निर्णय कई सवाल खड़े कर रहा है। कोटवारों ने ज्ञापन में मांग की है कि तहसीलदार द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश को तत्काल निरस्त कर सभी प्रभावित कोटवारों को बढ़ाई गई सेवा अवधि तक पुनः कार्य पर रखा जाए। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसील अध्यक्ष राजेन्द्र भालाधरे, उपाध्यक्ष संतोष मेश्राम, सविता रामटेके सहित बड़ी संख्या में कोटवार एवं संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भिलाई रोड़ मुख्य मार्ग पर बने गड्ढे करा रहे चन्द्रमा पर होने का एहसास!

पद्मेश न्यूज। लांजी। पहली नजर में यह दृश्य किसी नगर की सड़क का नहीं, बल्कि चंद्रमा की सतह पर होने का आभास कराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां वैज्ञानिक नहीं, बल्कि रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरने वाले हजारों राहगीर मौजूद हैं। नगर के सबसे व्यस्त लांजी-भिलाई मुख्य मार्ग पर फूड कैपिटल रेस्टोरेंट के समीप सड़क गड्ढों में इस कदर तब्दील हो चुकी है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच कहीं सड़क बची है। बारिश के बाद इन गहरे गड्ढों में भरा पानी खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। बाहर से आने वाले वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा तक नहीं लग पाता और पलभर की चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नगरवासियों के लिए यह बदहाली अब मजबूरी बन चुकी है, लेकिन पहली बार गुजरने वालों के लिए यह रास्ता किसी परीक्षा से कम नहीं।

सुबह से देर रात तक रहती है वाहनों की आवाजाही

सबसे गंभीर बात यह है कि यह कोई सुनसान मार्ग नहीं, बल्कि ऐसा महत्वपूर्ण तिराहा है जहां से एक मार्ग राज्य मार्ग को जोड़ता है तो दूसरा सीधे नगर के भीतर प्रवेश करता है। आसपास निजी लॉन, रेस्टोरेंट सहित अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण यहां सुबह से देर रात तक वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। विडंबना यह है कि यह सड़क नगर परिषद के अधीन है और इसी मार्ग से नगर परिषद के अधिकारी एवं इंजीनियर प्रतिदिन कार्यालय आते-जाते हैं। सवाल यह है कि क्या उन्हें यह बदहाल सड़क दिखाई नहीं देती? क्या उनकी जिम्मेदारी केवल कार्यालय की चारदीवारी और फाइलों तक सीमित है? विकास कार्यों की निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी तो उनकी नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

हर गुजरते दिन में हादसे की आशंका

इस मार्ग की दुर्दशा को लेकर पूर्व में भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से नगर परिषद का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। न गड्ढे भरे गए और न ही सड़क की मरम्मत की दिशा में कोई ठोस पहल की गई। ऐसे में हर गुजरता दिन इस मार्ग पर किसी बड़े हादसे की आशंका को और गहरा कर रहा है। इसके बाद भी अगर जिम्मेदारों ने इस व्यस्ततम मार्ग की सुध नहीं ली तो बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं व्यापारियों का कहना है की बारिश के कारण सड़क में उभरे इन गड्ढों में भरा गंदा पानी पैदल चलने वाले लोगों के लिये भी बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है तेज गति के वाहन जब इन गड्ढों से गुजरते है तो सड़क किनारे चलने वाले राहगीरों पर इन गड्ढों का पानी उछल जाता है जिससे उनके कपड़े तो खराब होते ही है वह भी दुर्घटना का शिकार होते होते बच रहे हैं।

इनका कहना है...

उक्त मार्ग पर उभरे गड्ढों के संबंध में मुझे पूर्व से ही जानकारी है और शिकायते भी लगातार मिल रही है, मेरे द्वारा दो से तीन दिनों के भीतर लांजी-भिलाई मार्ग में उभरे गड्ढों की मरम्मत करा दी जाएगी।

अमित नगपुरे, इंजीनियर
नगर परिषद, लांजी

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

बाबा रामदेव और रिलायंस को मप्र सरकार का झटका!

पीथमपुर में 419 एकड़ जमीन छीनने की कार्रवाई शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश के औद्योगिक हब पीथमपुर में बड़े-बड़े दावों और वादों के साथ जमीनें हासिल करने वाले महा-निवेशकों की मनमानी पर प्रदेश सरकार ने अब एक्शन लिया है। पिछले 10 सालों में पंतजलि, रिलायंस, एडीएजी और जापानी निवेशकों को आवंटित की गई 419 एकड़ की कीमती औद्योगिक जमीन सरकार वापस लेने जा रही है।

करोड़ों के निवेश और हजारों नौकरियों का ढिंढोरा पीटकर जमीन दबाने वाली इन कंपनियों से अब मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जमीन वापस लेकर नए और गंभीर निवेशकों को सौंपने की तैयारी में जुट गया है।

पंतजलि का फूड पार्क कागजों में सिमटा

पंतजलि को साल 2017 में 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत से करीब 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। दावा किया गया था कि 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे 5 हजार स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और पास्ता प्लांट का निर्माण किया जाएगा। वहीं 9 साल बीत जाने के बाद भी जमीन पर एक ईंट नहीं रखी गई। अब उद्योग विभाग ने बाबा रामदेव की पंतजलि कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर जमीन वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी है।

रिलायंस का डिफेंस प्रोजेक्ट हवा-हवाई

रिलायंस को पीथमपुर में लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। जिसको लेकर दावा किया गया था कि देश का बड़ा रक्षा उत्पादन संयंत्र, डेटा सेंटर और हथियार निर्माण की इकाई लगाई जाएगी। यह दावा किया गया था कि 46,000 करोड़ का बड़ा निवेश आएगा। आवंटन के समय 3 साल के भीतर उत्पादन शुरू करने की सख्त शर्तों थी लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी एक संयंत्र शुरु नहीं हुआ। अब इस आरक्षित जमीन का बड़ा हिस्सा निरस्त कर अन्य कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है।

जापानी निवेशकों के लिए रिजर्व 178 एकड़ जमीन पर भी बट्टा

पीथमपुर में जापानी और दक्षिण-पूर्व एशियाई ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए 178 एकड़ जमीन आरक्षित रखी गई थी। साल 2019 में जापानी संगठन जेट्रो की टीम ने दौरा भी किया था लेकिन सालों बाद भी कोई ठोस प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरा। अब इस जमीन को भी फ्र कर नए प्रस्तावों के लिए खोला जा रहा है।

इंफोसिस से छीनी 50 एकड़ जमीन

मध्य प्रदेश उद्योग विभाग अब ऐसी किसी भी कंपनी को बख्शने के मूड में नहीं है जो केवल जमीन रोककर बैठी है। इससे पहले इंफोसिस को इंदौर सुपर कॉरिडोर पर दी गई 130 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन वापस ली जा चुकी है। एशियन पेंट्स और अन्य 32 एकड़ वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। आगामी इन्वेस्टर समिट्स से पहले सरकार पीथमपुर और प्रदेश भर में खाली पड़े औद्योगिक प्लॉटों का पुनरावलोकन कर रही है जिससे वास्तविक निवेशकों को जमीन दी जा सके और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो।

राहुल गांधी की हिरासत पर मप्र विधानसभा में कांग्रेस का विरोध

- काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधायक... पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के सभी विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने तथा छात्रों के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि यदि पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर सदन में चर्चा नहीं कराई गई तो उसका विरोध आगे भी जारी रहेगा।

विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधी। साथ ही उन्होंने राज्य में पेपर लीक के मामलों और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जिनका सीधा संबंध युवाओं और छात्रों के भविष्य से है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे थे। उनके हाथों पर और बाजुओं पर काली पट्टी बंधी थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना उचित नहीं है। उनका आरोप था कि राहुल गांधी की हिरासत इसी मानसिकता का हिस्सा है और सरकार असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों के आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

एम.बी.बी.एस. इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए-दिग्विजय सिंह

भोपाल । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के एम.बी.बी.एस. इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड वर्तमान 14,337 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।

सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश के एम.बी.बी.एस. इंटर्न्स के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट कर बताया कि प्रदेश में शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 3,655 एम.बी.बी.एस. इंटर्न्स हैं, जिनमें से 2,055 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद उन्हें देश के अनेक राज्यों की तुलना में अत्यंत कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश में एम.बी.बी.एस. की वार्षिक ट्यूशन फीस लगभग 1 लाख रुपये है, जबकि इंटर्न्स को मात्र 14,337 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इसके विपरीत तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत कम फीस होने के बावजूद इंटर्न्स को कहीं अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश एम.बी.बी.एस. की फीस के मामले में देश में पांचवें स्थान पर है, जबकि इंटर्न्स को स्टाइपेंड देने के मामले में लगभग 25वें स्थान पर है। यह स्थिति प्रदेश सरकार की चिकित्सा शिक्षा और छात्रों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के एम.बी.बी.एस. इंटर्न्स की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके स्टाइपेंड को बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहयोग मिल सके और वे बिना आर्थिक दबाव के बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित हों।

दिग्विजय सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों मेडिकल छात्रों को राहत प्रदान करेंगे।

गरीब बच्चों की पढ़ाई पर संकट

आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति अटकी, टीसी के लिए स्कूल मांग रहे पैसे

भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के हजारों विद्यार्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दो शैक्षणिक सत्रों 2024-25 और 2025-26 की फीस प्रतिपूर्ति राशि निजी स्कूलों को अब तक जारी नहीं की गई है। इसका असर अब बच्चों की पढ़ाई और स्कूल बदलने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। कई निजी स्कूल प्रबंधन फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने का हवाला देते हुए विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) देने से इनकार कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों द्वारा टीसी जारी करने के लिए लंबित फीस और अन्य शुल्क जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है और इसके बदले राज्य सरकार स्कूलों को निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति करती है। प्रदेश में इस मद में हर साल करीब 400 करोड़ रुपये की राशि निजी स्कूलों को दी जाती है, लेकिन पिछले दो वर्षों से भुगतान लंबित होने के कारण स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार जल्द भुगतान नहीं करती है तो आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश और उनकी निरंतर शिक्षा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

बिना भुगतान के खर्च उठाना मुश्किल

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार से फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि आरटीई के बच्चों की शिक्षा, स्टाफ और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च स्कूलों को उठाना पड़ रहा है। स्कूल संचालकों की मांग है कि या तो सरकार जल्द लंबित भुगतान करे या फिर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की सीट पर नए प्रवेश की अनुमति दी जाए, ताकि आर्थिक नुकसान कम हो सके।

छह साल में घटे आरटीई प्रवेश

गौरतलब है कि आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में भी गिरावट देखने को मिली है। 2021-22 में 1,99,741 पात्र आवेदनों में से 1,29,690 बच्चों को प्रवेश मिला था। करीब 70 हजार बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए थे। 2026-27 में 2,10,422 आवेदन आए, जिनमें 1.78 लाख आवेदन पात्र पाए गए। पहले चरण में केवल करीब 97 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सका। आंकड़े बताते हैं कि आवेदन बढ़ने के बावजूद प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है।

टीसी के लिए अभिभावक परेशान

मिली जानकारी के अनुसार, कई छात्रों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पा नगर स्थित एमपी विकास कान्वेंट स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ने वाली छात्रा गरिमा यादव ने पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया। लेकिन पुराने स्कूल ने फीस प्रतिपूर्ति लंबित होने का हवाला देते हुए टीसी देने से इनकार कर दिया। छात्रा के पिता राजकुमार यादव ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की है। रातीबड़ स्थित आइएएस स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ रही छात्रा के अभिभावक दीपक बाथम ने कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बेटी का दूसरे स्कूल में प्रवेश कराना है, लेकिन स्कूल प्रबंधन टीसी देने के बजाय लंबित राशि जमा करने का दबाव बना रहा है।

स्कूल एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि दो सत्रों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने से कई स्कूल संचालक आरटीई विद्यार्थियों को पढ़ाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतान की मांग को लेकर आने वाले दिनों में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एमपी विकास कान्वेंट के संचालक प्रेम ठाकुर का कहना है कि दो साल से शासन से फीस नहीं मिली है। यदि विद्यार्थी बीच सत्र में स्कूल छोड़ते हैं तो स्कूल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ गतिविधियों की फीस बकाया होने के बाद ही टीसी जारी की जाएगी।

सरकार के भुगतान पर टिकी आरटीई व्यवस्था

आरटीई का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा का अवसर देना है, लेकिन फीस प्रतिपूर्ति में देरी से अब वही विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेश में आरटीई व्यवस्था पर भरोसे का संकट खड़ा हो सकता है।

कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले भाजपा नेताओ को पुलिस ने रोका

भोपाल। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के निकट राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में बुधवार को राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओ ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता टी-शर्ट पहनकर हाथों में तख्तियां लेकर दोपहर करीब एक बजे रेड क्रॉस अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय की ओर पैदल मार्च के लिए निकले। कार्यकर्ताओ के साथ विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि दुबे और अन्य कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े। हालांकि पहले से ही स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये तैनात भारी पुलिस बल ने सभी को रेडक्रॉस अस्पताल के सामने लिंक रोड पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। सुरक्षा के चलते कांग्रेस कार्यालय के चारों और भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं आसपास के रास्तो पर भी बैरिकेडिंग की गई। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने के लिये बैरिकेडिंग फांदने का प्रयास किया। उन्हें रोक रही पुलिस टीम और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। हेमंत खंडेलवाल ने कहा, अभी हम चेतावनी देने आए थे। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी, तो आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे।

विधानसभा में केन-बेतवा परियोजना के मुआवजे का उठा मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष बोले

प्रभावित ग्रामीणों को नहीं पर्याप्त मुआवजा

भोपाल । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छतरपुर और पन्ना जिले के प्रभावित ग्रामीणों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा तय करने में भी गड़बडियां हुई हैं। जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि पन्ना जिले के सात गांवों के 1,321 परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये दिए गए हैं। सरकार के अनुसार मुआवजा तय करने और पुनर्वास लाभ के वितरण में कोई अनियमितता नहीं मिली है।

मंत्री ने बताया कि छतरपुर जिले में पहले 3,080 परिवारों को पुनर्वास का लाभ मंजूर किया गया था। बाद में गांव-गांव सर्वे के बाद 638 अतिरिक्त परिवारों को भी निर्धारित राशि स्वीकृत कर दी गई। इस पर उमंग सिंघार ने पूछा कि अभी कितने प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलना बाकी है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी सदन के पटल पर रखने की मांग की, जिस पर मंत्री ने अध्यक्ष के निर्देशानुसार जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सदन में कहा कि पन्ना जिले में अब केवल दो परिवारों को मुआवजा दिया जाना बाकी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 638 परिवार अब भी पुनर्वास सूची से बाहर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिंघार ने कहा कि जो लोग गांव में नहीं रहते, उन्हें 8 से 10 करोड़ रुपये तक का मुआवजा मिल गया, जबकि गांव में रहने वाले कई पात्र परिवार अब भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

सीएम ने दोबारा जांच का दिया भरोसा

सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों का जबरन विस्थापन कराया जा रहा है और विरोध करने पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने तक विस्थापन की कार्रवाई रोकी जाए। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि मुआवजा वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी या विसंगति हुई है तो सरकार पूरे मामले की दोबारा जांच कराएगी।

पुन: जांच की मांग

उमंग सिंघार ने कहा कि 11 हजार से अधिक लोगों को करीब 8 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा गया है। उन्होंने पूछा कि जब अभी भी कई लोगों को मुआवजा मिलना बाकी है, तो परियोजना की आगे की कार्रवाई और लोगों का विस्थापन कैसे किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की।

बस किराया बढ़ाने पर निर्णायक आर-पार की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में बस किराया बढ़ाने की मांग अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। लगातार आश्वासनों के बावजूद किराया संशोधित नहीं होने से नाराज मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 26 जुलाई को सागर में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश के सभी 55 जिलों से कम से कम पांच-पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें किराया वृद्धि, 7 जुलाई को प्रकाशित राजपत्र में राष्ट्रीयकरण की स्कीम सहित बस संचालकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन ने बताया कि बैठक सागर के भोपाल रोड स्थित आदर्श गार्डन (मोतीनगर थाना के पास) में दोपहर एक बजे आयोजित होगी। प्रदेशभर के बस संचालकों की मौजूदगी में सरकार के रुख की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन और प्रदेशव्यापी हड़ताल की रूपरेखा भी तय की जा सकती है। बस संचालकों का कहना है कि परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से कई दौर की चर्चा के दौरान किराया बढ़ाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ। इस बीच डीजल, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, फिटनेस, टायर और अन्य परिचालन खर्च लगातार बढ़ते गए हैं, जिससे बस संचालन आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में भी किराए का पुनरीक्षण किया जा चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी बस किराए में वृद्धि करते हुए इसे करीब दो रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तक कर दिया है। ऐसे में मध्यप्रदेश में वर्षों से किराया नहीं बढ़ने से बस संचालकों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। सागर की बैठक में बस संचालक यह भी तय करेंगे कि यदि सरकार जल्द किराया वृद्धि पर निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को किस स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए। प्रदेशभर के ऑपरेटरों की नजर अब इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि यहीं से आगामी संघर्ष की दिशा तय होने की संभावना है।

कांग्रेस के विरोध में भाजपा का मार्च, हेमंत खण्डेलवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने रेडक्रॉस अस्पताल से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक विरोध मार्च निकालकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के निकट किए गए धरना और हंगामे के विरोध में आयोजित किया गया।

प्रदर्शन के दौरान श्री खण्डेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय अराजकता की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी मंचों पर भारत, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भाजपा राष्ट्रहित, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत विपक्ष छात्रों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संवाद के बजाय टकराव की राजनीति में विश्वास रखता है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विरोध मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस कार्यालय के निकट पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर मार्च को रोक दिया गया।

वन विभाग में पदोन्नति सूची निरस्त, संशोधित सूची जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश के वन विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। खंडवा वन वृत्त में पदोन्नति में अनियमितताओं की शिकायत सही पाए जाने के बाद 13 जुलाई 2026 को जारी पदोन्नति सूची निरस्त कर 20 जुलाई को संशोधित सूची जारी करनी पड़ी। इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच ने पूरे विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वन विभाग में पदोन्नतियों के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण कई पात्र वन कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा वंचित कर्मचारियों को उनका वैधानिक पदोन्नति लाभ दिया जाए।

मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि खंडवा वन वृत्त में शिकायत के बाद हुई जांच में पदोन्नति प्रक्रिया में गंभीर गड़बडियां सामने आईं। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक, खंडवा वृत्त ने 13 जुलाई को जारी पदोन्नति सूची निरस्त कर 20 जुलाई को वनरक्षक से वनपाल तथा वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल पदों की संशोधित पदोन्नति सूची जारी की। नई सूची में ऐसे दर्जनों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, जिन्हें पहले अपात्र घोषित कर सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि संगठन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायतें और ज्ञापन सौंपे थे, जिसके बाद जांच कराई गई और अनियमितताएं सही पाई गईं।

अनुराग जैन बने नीति आयोग के सीईओ

भोपाल। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बुधवार को जारी आदेश में 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार, वे पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल उनकी स्वीकृत सेवा-विस्तार अवधि तक और उसके बाद अधिकतम दो वर्ष अथवा अगले आदेश तक रहेगा, जो भी पहले हो।

अनुराग जैन मूल रूप से 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति से ठीक पहले एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया था। इसके बाद उनका वर्तमान कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक निर्धारित है। पिछले कुछ सप्ताह से यह चर्चा चल रही थी कि क्या उन्हें मुख्य सचिव के रूप में एक और सेवा विस्तार मिलेगा या राज्य को नया मुख्य सचिव मिलेगा। अब नीति आयोग के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद यह अटकलें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। अनुराग जैन अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। इससे पहले वे केंद्र सरकार में सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी, नौकरशाही में बेहतर समन्वय और केंद्र व राज्य सरकार के बीच मजबूत तालमेल को उनकी प्रमुख उपलब्धियों में माना गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उनकी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से लगातार हुई बैठकों को भी उनके सेवा विस्तार की एक अहम वजह माना गया। ग्वालियर निवासी अनुराग जैन ने आईआईटी खडग़पुर से बीटेक और अमेरिका के मैक्सवेल स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे भोपाल कलेक्टर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

बड़वानी की लाल मिर्च को मिलेगा जीआई टैग

भोपाल/बड़वानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बड़वानी अपनी मेहनतकश किसानों और कृषि नवाचारों के दम पर देश में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होकर किसानों को शुभकामनाएं दीं और आधुनिक खेती अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार बड़वानी की लाल मिर्च को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिससे इसे वैश्विक पहचान और बेहतर बाजार मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं से 319 गांवों की 1.21 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

हरारे । श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को यहां मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरु हो रहे पहले टी20 मैच में जीत से शुरुआत करने उतरेगी। भारतीय टीम को इस दौरे में तीन मैचों की सीरीज खेलनी है। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में हार मिली थी जिसके बाद से ही नये कप्तान श्रेयस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में श्रेयस का लक्ष्य इस सीरीज के सभी मैच जीतकर अच्छी वापसी करना रहेगा। इस दौरे के लिए भारतीय टीम में कई युवाओं को अवसर मिला है जो बेहतर प्रदर्शन कर अपने को साबित करना चाहेंगे। भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को इस दौरे में पिछली असफलतों से सबक लेते हुए उछाल भरी पिचों पर ध्यान से खेलना होगा।

वहीं दूसरी ओर, मेजबान जिम्बाब्वे की टीम ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था जिससे वह आत्मविश्वास से भरी हुई है, जिससे भारतीय टीम के लिए सीरीज आसान नहीं रहेगी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का

भी कहना है कि भारतीय टीम उन्हें हल्के में लेने की भूल न करे और ये मुकाबला बराबरी का रहेगा।

इस सीरीज में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी। 15 वर्षीय यह बल्लेबाज एक बार फिर आकर्षण का केंद्र होगा। संजू सैमसन के इस दौरे का हिस्सा न होने के कारण वैभव अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। हरारे का यह मैदान वैभव के लिए बेहद खास है। इसी मैदान पर उन्होंने इसी साल फरवरी में अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभिषेक शर्मा ने भी इसी मैदान पर अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक लगाया था, जिससे इस जोड़ी से यहां बड़ी पारी की उम्मीदें होंगी।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगरावा अपनी गति और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को इन दोनो से सावधान रहना होग। भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में बेहद संभलकर खेलना होगा ताकि बड़े स्कोर की नींव रखी जा सके और मध्यक्रम पर दबाव कम हो।

भारतीय टीम प्रबंधन के सामने अंतिम ग्यारह का चयन भी एक बड़ी चुनौती होगा, खासकर ऑलराउंडर संयोजन को लेकर। शिवम दुबे, हर्ष दुबे और सूर्यांश शेडगे में से किसे मौका मिलेगा, इस पर फैसला आसान नहीं होगा। वहीं, तेज गेंदबाजी विभाग में मयंक यादव और प्रिंस यादव का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि तीसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए यश ठाकुर और आशीष शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है। यह सीरीज युवा भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगामी बड़े मुकाबलों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगी।

दोनों की संभावित टीमें

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, आशीष शर्मा, प्रभसिमरन सिंह।

जिम्बाब्वे- सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तडीवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगरावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्ज़वा त्सिगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स आज से

-स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 125 भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे

ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस बार 74 देशों के 3000 से अधिक एथलीट 10 खेलों की 215 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से करीब 125 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, जिनमें ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, विश्व चैंपियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन समेत कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं।

इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में अलग होंगे। पहले इन खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर को करनी थी, लेकिन आयोजन की बढ़ती लागत के कारण उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लास्गो को सौंपी गई। खर्च और समय को ध्यान में रखते हुए इस बार खेलों का आकार भी छोटा रखा गया है और केवल 10 प्रमुख खेलों को ही कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें 6 पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, जिससे दिव्यांग खिलाडियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रंगारंग उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 10-30 बजे शुरू होगा। भारतीय दल की अगुवाई ध्वजवाहक के रूप में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन करेंगी।

इन भारतीय खिलाडियों पर भी रहेंगी निगाहें

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की उम्मीदें सिर्फ नीरज चोपड़ा तक सीमित नहीं हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, जैसमीन लंबोरिया, जबकि एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर, तेजस्विन शंकर, सीमा पुनिया और प्रियंका गोस्वामी से भी पदक की उम्मीद रहेगी।

टेस्ट से संन्यास के बाद मैदान में उतरे स्टोक्स ने घरेलू क्रिकेट में लगाया शतक

लंदन । हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अब घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए पहले ही मैच में शतक लगाया है। स्टोक्स ने ये शतक घरेलू वन-डे कप में डरहम की ओर से खेलते हुए लगाया। स्टोक्स ने इस दौरान डर्बीशायर के खिलाफ नाबाद 108 रन बनाये। संन्यास के बाद पहली बार मैदान में लौटे स्टोक्स ने अपनी इस पारी से दिखाया है कि अभी भी उनमें काफी क्रिकेट बचा है। इस मैच में 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टोक्स ने डरहम की ओर से खेलते हुए 108 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। उनकी यह पारी शतक के साथ ही जुझारूपन और दृढ़ संकल्प भी दिखाती है। मैच के दौरान स्टोक्स क्रैंप्स से जूझते रहे पर उन्होंने हार नहीं मानी और बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। काउंटी के लिस्ट ए मुकाबले में यह उनका 12 साल के बाद का पहला शतक है।

बीसीसीआई ने घरेलू किकेट के लिए नियमों में किया बदलाव

जानबूझकर नो-बॉल फेंकी तो मैच से बाहर होगा गेंदबाज

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेल क्रिकेट के नीयमों में बदलाव की घोषणा कही है। बोर्ड ने आगामी 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीज़न के लिए खेल के नियमों में ये बदलाव इसे और बेहतर बनाने के लिए किये हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव ये है कि अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर फ्रंट-फुट पर नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग गेंद करता है, तो उसे केवल उस पारी से नहीं, बल्कि पूरे मैच से निलंबित कर दिया जाएगा। ये बदलाव खेल की अखंडता और रणनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए किये गये है। ये बदलाव मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की सिफारिशों को देखते हुए किया गया है। वहीं अब तक दोषी गेंदबाज को केवल उस पारी में गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि, अब मैदानी अंपायर यदि यह निर्धारित करते हैं कि किसी गेंदबाज ने जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग गेंदबाज की है, तो उसे उस पूरे मैच में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह कदम खेल में अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों को रोकने के लिए उठाया गया है।

वहीं दिन के खेल के समाप्त होने से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। अब से, यदि दिन के आखिरी ओवर के दौरान कोई विकेट गिरता है, तो खेल वहीं समाप्त नहीं होगा। इसकी जगह ओवर पूरा कराया जाएगा, जिससे नई बल्लेबाजी करने वाली टीम को दिन के अंत में क्रीज पर तुरंत आने की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह परिवर्तन खेल को और अधिक गतिशील बनाने में मदद करेगा।

नियम 15.2 के तहत, अब किसी भी टीम को मैच की अंतिम पारी में पारी घोषित ने की अनुमति नहीं होगी। एमसीसी का मानना था कि इस नियम का दुरुपयोग करके कुछ टीमें कृत्रिम परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करती थीं, जो खेल की वास्तविक भावना के खिलाफ था। यह बदलाव खेल के स्वाभाविक प्रवाह को बनाए रखने के लिए है।

वहीं घरेलू एकदिवसीय मैचों में अब मुख्य कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से सीधे बातचीत करने की राहत मिल गई है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुरूप है, ताकि कोच खिलाड़ियों को रणनीतिक सलाह तुरंत दे सकें और मैच की परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाने में मदद कर सकें।

इसके अलावा विकेटकीपरों के लिए भी नियम आसान कर दिए हैं। अब उन्हें गेंदबाज के रन-अप शुरू होने से ही अपने दस्ताने विकेट के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल गेंद फेंकते समय उनके दस्ताने विकेट के पीछे होने चाहिए, जिससे विकेटकीपरों को अधिक सहजता और लचीलापन मिलेगा, साथ ही खेल के प्रवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। ये सभी संशोधित नियम अगले महीने दलीप ट्रॉफी से शुरू होने वाले 2026-27 घरेलू सीज़न से लागू होंगे।

वॉर्नर को ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में 18 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वार्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में अगले माह 18 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार किए गए वॉर्नर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वॉर्नर पर आरोप था कि वह एक वैन चला रहे थे और एक रैंडम टेस्टिंग साइट से ठीक पहले रुके थे। इसके बाद जब उनकी जांच हुई तो पाया गया कि उन्होंने तय सीमा से अधिक शराब पी रखी थी। वॉर्नर खुद गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, इसके बाद से ही यह मामला कोर्ट में लंबित था और अब वॉर्नर ने इसमें अपनी गलती मान ली है। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान वॉर्नर स्वयं कोर्ट नहीं पहुंचे थे। उनकी ओर से उनके वकील बॉबी हिल सिडनी की अदालत में पेश हुए और मिडिल रेंज ड्रिंक-ड्राइविंग के अपराध को स्वीकार करने की अर्जी दी।

पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम है एक अनोखा रिकार्ड

मुम्बई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान अपने दौर के एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के साथ सलामी जोड़ीदार के तौर पर उन्होंने कई बड़े साझेदारियां बनायी हैं। वह बदकिस्मती से एक भी शतक नहीं लगा पाये पर इसके बाद भी उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 2000 से अधिक रन है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेतन ने अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 2084 रन बनाए, जबकि 7 एकदिवसीय मैचों में 153 रन बनाये। उनकी बल्लेबाजी की अनूठी बात यह थी कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी शतक नहीं लगा पाए। कई मौकों पर वह शतक के बेहद करीब आकर भी पूरा नहीं कर पाये। वह 9 बार 80 से 97 के बीच के स्कोर पर आउट हुए। वह टेस्ट क्रिकेट में बिना शतक लगाए 2000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, ये अपने आप में एक अनोखा और अविश्वसनीय रिकॉर्ड था।

इस बल्लेबाज ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 179 मैच खेले और 40 की प्रभावशाली औसत से 11,143 रन बनाए, जिसमें 21 शानदार शतक और 59 अर्धशतक शामिल थे। घरेलू सर्किट में उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 1978 में भारतीय टीम में जगह मिली जहां वह गावस्कर के सलामी जोड़ीदार के तौर पर उतरे।

इस बल्लेबज ने साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने साथी सलामी बल्लेबाज और तत्कालीन कप्तान सुनील गावस्कर को पांच साल के प्रतिबंध से भी बचाया था। अगर वह नहीं बचाते तो गावस्कर का करियर समाप्त होना तय था।

हालांकि उनको उस घटना के लिए याद किया जाता है जो 1981 में मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली की एक गेंद पर अंपायर ने गावस्कर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। गावस्कर अंपायर के इस फैसले से इतने नाराज़ और असहमत थे कि उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गावस्कर गुस्से में अपने सलामी जोड़ीदार चेतन चौहान का हाथ पकड़कर मैदान से बाहर जाने लगे, मानो वह मैच का बहिष्कार करना चाहते हों। यह एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय घटना बन सकती थी, जिससे भारतीय क्रिकेट की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता था।

इसी समय पर चौहान ने असाधारण सूझबूझ और शांतचित्तता का परिचय दिया। उन्होंने गावस्कर के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया और साथ ही टीम इंडिया के तत्कालीन मैनेजर शाहिद अली खान दुर्रानी को मैदान की तरफ आने के संकेत किये। दुर्रानी के समझाने-बुझाने के बाद ही गावस्कर शांत हुए और मामला सुलझा। वहीं अगर चेतन चौहान ने उस समय इतनी बुद्धिमत्ता और धैर्य न दिखाया होता और गावस्कर को मैदान से बाहर जाने दिया होता, तो उनके इस गंभीर व्यवहार के लिए गावस्कर पर कम से कम पांच साल का प्रतिबंध लग सकता था, जो उनके शानदार करियर को समय से पहले ही समाप्त कर देता।

रोहित फिर बन सकते हैं मुम्बई इंडियंस के कप्तान ?

लंदन । भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में शानदार शतकीय पारी खेलकर एक ओर जहां अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। वहीं उनके सीरीज के बाद भी यहीं रुकने से कई प्रकार की अटकलें लगायी जा रही हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी से भी हुई। इससे अनुमान लगाये जा रहे हैं कि वह एक बार फिर मुम्बई इंडियंस की कप्तानी संभाल सकते है।

रोहित की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। दो साल पहले फ्रेंचाइजी अचानक ही रोहित को हटाकर हार्दिक पंड्या को टीम का कप्तान बनाया था। उसके बाद से ही टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वह एक भी बार नहीं जीत पायी है। इससे आगामी सत्र से पहले कप्तान बदलने की मांग तेज हो गयी है। ऐसे में रोहित को एक बार फिर कप्तान बनाने की अटकलें तेज हो गयी हैं। प्रशंसकों के बीच ही यह सवाल घूम रहा है कि क्या मुंबई इंडियंस अपने पुराने और सफल कप्तान पर फिर से भरोसा जताएगी? इसका कारण है कि कप्तानी की इस दौड़ में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर रोहित को दोबारा मुंबई की कमान संभालने का प्रस्ताव मिलता है, तो क्या वह इसे स्वीकार कर टीम को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएंगे, या फिर तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी को भविष्य के लिए तैयार करने का फैसला करेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा, लेकिन इस मुलाकात ने मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों की उम्मीदें जरुर जगा दी हैं।

एफआईएच एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारतीय लड़कों और लड़कियों ने अपने मुकाबले जीते

मस्कट । यहां जारी एफआईएच एशियन चैंपियनशिप में भारतीय लड़कों और लड़कियों ने शानदार जीत हासिल की। लड़कों की सब जूनियर हॉकी टीम ने जहां पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में 7-4 से हराया। वहीं एक अन्य मुकाबले में ओमान को 14-0 से पीटा। दूसरी ओर एक अन्य मामले में भारतीय लड़कियों ने भी शानदार खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। वहीं चीन के साथ 2-2 से उसका मुकाबला बराबरी पर रहा। भारतीय टीम ने पाक के खिलाफ मुकाबले में आक्रामक रुख अपनाया। करण गौतम ने 5वें, 9वें और 19वें मिनट में शानदार गोल दागकर हैट्रिक लगायी। उनके अलावा, राहुल यादव (3), प्रहलाद राजभर (10), कप्तान केतन कुशवाहा (11) और रोमित पाल (11) ने भी एक-एक गोल किया। वहीं पाक

की ओर से असलम मुहम्मद फरहान (6), अदील (8) और उस्मान मुहम्मद (10, 16) ने गोल किए, लेकिन वे भारत की बढ़त को कम नहीं कर पाए और अंततः 7-4 से मुकाबला हार गए। एक अन्य मुकाबले में भारतीय लड़कों ने मेजबान ओमान पर आसानी से 14-0 की जीत हासिल की। इस मैच में कप्तान केतन कुशवाहा ने स्वयं चार गोल (6, 11, 15, 20) दागे। आशीष तानी पूर्ति (1, 16, 19) ने हैट्रिक लगायी जबकि राहुल यादव (2, 12) और शाहरुख अली (3, 13) ने दो-दो गोल किए। प्रहलाद राजभर (9), करण गौतम (15) और रोमित पाल (18) भी गोल करने वालों में शामिल रहे, जिससे टीम का आत्मविश्वास और बढ़ा। वहीं सब-जूनियर लड़कियों की टीम ने भी चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल दिखाते हुए चीन से 2-2 से ड्रॉ खेला। इसके बाद, भारतीय लड़कियों ने उज्बेकिस्तान पर 16-0 की शानदार जीत के साथ दिन का समापन किया। इस मैच में नौशीन नाज ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाते हुए चार गोल (6, 9, 15, 16) किए। कप्तान स्वीटी कुजूर (10, 13, 20) और संदीपा कुमारी (2, 6, 20) ने प्रभावशाली हैट्रिक लगाईं।

अफगानिस्तान एकदिवसीय टीम के कप्तान शाहिदी का इस्तीफा

काबुल । अफगानिस्तान के बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी ने एकदिवसीय टीम की कप्तानी छोड़ दी है। अफगानिस्तान टीम को हाल ही में भारत के खिलाफ सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इसी से निराश होकर शाहिदी ने ये कदम उठाया है। शाहिदी ने अपने करियर के दौरान 55 एकदिवसीय मैचों में टीम का नेतृत्व किया है।

शाहिदी ने सोशल मीडिया में अपने संन्यास को लेकर अपनी पोस्ट में लिखा, काफी सोच-विचार के बाद मैंने अपनी टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इस टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है। उन्होंने इस यात्रा में भरोसा रखने और समर्थन देने के लिए मैनेजमेंट, कोच, टीम के साथियों और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त किया। शाहिदी ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे कप्तान का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर टीम की सेवा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने नए कप्तान व टीम के लिए भविष्य में सफलता की कामना की। शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान ने कुल 55 एकदिवसीय मैचों में से 27 में जीत हासिल की है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में आयोजित 2023 पुरुष एकदिवसीय विश्व कप में टीम का शानदार प्रदर्शन। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने क्रिकेट दिग्गजों इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ यादगार जीतें दर्ज कीं और सेमीफाइनल में जगह बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था।

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वैभव बना सकते हैं एक रिकार्ड

हरारे । भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को यहां तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच खेलने उतरेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच में जीत के साथ शुरुआत करना रहेगा। अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में इंग्लैंड और आयरलैंड में मिली पिछली हार को भुलाकर जीत की राह पर लौटना चाहेगी। 15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी इस सीरीज में प्रशंसकों की नजरें रहेंगी। वैभव हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। इंग्लैंड दौरे पर वह बड़ी पारी नहीं खेल पाये थे। अब जिम्बाब्वे में उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद है।

वैभव के पास इस सीरीज में एक बड़ा रिकार्ड भी अपने नाम करने का अवसर है। वैभव ने अबतक 37 टी20 क्रिकेट मैचों में 139 छक्के लगाये हैं। ऐसे में उन्हें अपने 150 छक्के पूरी करने के लिए केवल 11 छक्के और चाहिये। इस सीरीज में अगर वह ये उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे तो सबसे तेजी से 150 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।

अभी सबसे तेजी से 150 छक्के का विश्व रिकॉर्ड यूएई के बल्लेबाज मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज है, जिन्होंने 66 पारियां खेलते हुए टी20 क्रिकेट में अपने 150 छक्के पूरे किए थे। वहीं वैभव ने अभी तक केवल 37 पारियां खेली हैं। वसीम के बाद वेस्टइंडीज के दो विस्फोटक बल्लेबाजों, एविन लुईस और क्रिस गेल ने भी सबसे कम पारियो में 150 छक्के लगाये हैं। लुईस ने 70 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि गेल ने 72 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। भारतीय बल्लेबाजों में यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 में 150 छक्के पूरे करने के लिए 86 पारियां खेली हैं।

हेटमायर की साहसिक पारी से वेस्टइंडीज ने तीसरा एकदिवसीय जीता

जमैका । शिमरन हेटमायर की शानदार अर्धशतकीय पारी की सहायता से मेजबान वेस्टइंडीज ने पांच एकदिवीसय मैचों की सीरीज के अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को दो विकेट से हरा दिया। इस जीत में हेटमायर की अहम भूमिका रही। हेटमायर ने 64 गेंदों पर 69 रन बनाये। न्यूजीलैंड ने हालांकि यह सीरीज 3-2 से जीत ली है पर अंतिम मैच में हाथ आयी जीत फिसलने का मलाल उसे अंत तक याद रहेगा।

वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 9 रनों के अंदर ही अपने तीन विकेट खो दिए। टीम ने 247 रनों पर ही 8 विकेट खो दिये। टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरुरत थी। वहीं न्यूजीलैंड को जीत के लिए केवल दो विकेट की जरुरत थी। ऐसे दबाव के बीच भी हेटमायर डटे रहे। एक छोर से लगातार विकेटों के गिरने के बाद भी हेटमायर क्रीज पर डटे रहे।

269 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत सधी हुई रही थी। सलामी बल्लेबाजों ने एक अच्छी नींव रखी, लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने में विफल रहे। हेटमायर को शेरफेन रदरफोर्ड का साथ मिला। रदरफोर्ड ने अपनी 58 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी में 5 छक्के और 2 चौके जड़कर मैच का रुख पलटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाये। कीवी टीम की ओर से कप्तान टॉम लाथम ने 71 गेंदों में सबसे अधिक 69 रन बनाए, जबकि निक केली ने 80 गेंदों में 64 रन और विल यंग ने 63 गेंदों में 56 रनों का योगदान दिया। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, जिसे वे अंततः डिफेंड नहीं कर पाए।

ई20 पेट्रोल विवाद- गाड़ियों में खराबी की शिकायतों के बाद ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से की मांग

पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराई जाए

नई दिल्ली। देशभर में ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बीच अब इसकी गुणवत्ता को लेकर नया विवाद सामने आया है। कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी गाड़ियों में स्टार्ट होने में परेशानी, चलते-चलते इंजन बंद होने और परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। इन शिकायतों के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने केंद्र सरकार से पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले ईंधन की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की व्यवस्था बनाने की मांग की है। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि समस्या ई20 पेट्रोल नहीं, बल्कि दूषित ईंधन हो सकता है।

ई20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार इसका उपयोग इसलिए बढ़ा रही है ताकि, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, प्रदूषण में कमी आए, एथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाई जा सके और ग्रीन फ्यूल की तरफ बड़े कदम उठाए जा सकें। इसलिए वाहन निर्माताओं द्वारा नई ई20-कंप्लायंट गाड़ियों को इसी मिश्रण के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री के

अनुसार, यदि वाहन ई20 के लिए डिजाइन किया गया है तो सामान्य परिस्थितियों में उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां असल चिंता ईंधन में मिलावट या नमी को लेकर है। उद्योग का कहना है कि कई मामलों में जांच के दौरान ईंधन के नमूनों में सामान्य से अधिक पानी और क्लोराइड पाया गया है।

एथेनॉल की खासियत ही बन रही चुनौती

एथेनॉल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वातावरण से पानी आसानी से सोख लेता है। यदि पेट्रोल पंप के भूमिगत टैंक या पाइपलाइन में पानी पहुंच जाता है तो ई20 ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पानी पहुंचने के संभावित कारणों में बारिश का पानी, नमी, कंडेनसेशन, ईंधन टैंकरों के जरिए पानी का प्रवेश या पुराने स्टोरेज टैंक हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि भूमिगत टैंक में पानी की मात्रा 0.5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो एथेनॉल पेट्रोल से अलग होकर पानी के साथ मिल जाता है, जिसे फेज सेपरेशन कहा जाता है। इसके बाद ऊपर पेट्रोल की परत रह जाती है और नीचे पानी और एथेनॉल का मिश्रण जमा हो जाता है। यदि किसी वाहन में नीचे वाले हिस्से का ईंधन चला जाए तो इंजन में स्टार्टिंग, मिसफायरिंग और स्टॉलिंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं।

पुराने वाहनों पर उठे सवाल

उद्योग का कहना है कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ी है, लेकिन कई पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंक पुराने हैं और पाइपलाइन ई20 के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुई हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर माइल्ड स्टील स्टोरेज टैंक अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और पुराने टैंकरों से भी ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। माइल्ड स्टील के टैंक समय के साथ जंग पकड़ सकते हैं, जिससे ईंधन दूषित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग चाहता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच तेल विपणन कंपनियों के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। उद्योग का तर्क है कि, जो संस्था ईंधन बनाती और बेचती है, वही उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर रही है। इसके बजाय एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो बीआईएस मानकों के अनुसार ईंधन की जांच करे।

ई20 पेट्रोल में क्या नहीं होना चाहिए

भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ई20 पेट्रोल में अतिरिक्त डिटर्जेंट, डिस्पर्सेंट, सिलिकॉन, क्लोरीन आधारित एडिटिव और धातु आधारित एडिटिव नहीं होने चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वाहन ई20 कंप्लायंट है तो सामान्य परिस्थितियों में ई20 पेट्रोल सुरक्षित है। समस्या ईंधन में पानी, मिलावट या खराब स्टोरेज से जुड़ी हो सकती है। यदि वाहन में बार-बार स्टार्टिंग या इंजन बंद होने जैसी समस्या आए तो अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच करानी चाहिए।

जंतर मंतर का असर पटना तक दिखा, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन

-पुलिस पर बल प्रयोग और गांधी मैदान में रोकने का आरोप, छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

पटना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को पटना में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान के भीतर रोक दिया और बाद में बल प्रयोग किया।

आइसा और अन्य छात्र संगठनों के आह्वान पर छात्र जेपी गोलंबर पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें गांधी मैदान के अंदर जाने के बाद बाहर निकलने नहीं दिया गया। छात्रों के अनुसार, मैदान का 10 नंबर गेट नहीं खोले जाने पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों ने यह भी दावा किया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।

प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों और छात्राओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण विरोध को रोकने का प्रयास किया। उनका कहना था कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है तथा बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। उसी के समर्थन में पटना सहित अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, जिससे यह मुद्दा अब राष्टीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है।

हूती की धमकी के बीच भारत आ रहे टैंकरों ने बदला मार्ग

नई दिल्ली। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की नई धमकी के बाद सऊदी अरब से चीन और भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहे दो तेल टैंकरों ने लाल सागर (रेड सी) में अपना मार्ग बदल लिया। दोनों जहाज बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षा खतरे को देखते हुए उन्होंने यू-टर्न लेकर स्वेज नहर की दिशा में वापस रुख कर लिया। इस घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर नए संकट की आशंका पैदा हो गई है।

हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी थी कि सऊदी बंदरगाहों से माल लादने या उतारने वाले किसी भी जहाज को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर निशाना बनाया जा सकता है। इस चेतावनी के बाद कई जहाजों ने अपने तय मार्ग पर पुनर्विचार शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिन लॉन्ग यांग नामक सुपर टैंकर सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन के लिए रवाना हुआ था। बाब-अल-मंदेब के निकट पहुंचने से पहले ही जहाज ने दिशा बदलकर स्वेज मार्ग अपना लिया। इसी प्रकार भारत के लिए तेल लेकर जा रहा एक अन्य टैंकर भी उत्तर दिशा की ओर लौट गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा उत्पन्न होने के बाद सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के माध्यम से यनबू बंदरगाह तक तेल पहुंचाकर वहां से एशियाई देशों को भेज रहा है। यदि जहाज बाब-अल-मंदेब मार्ग का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें स्वेज नहर और उसके बाद अफ्रीका के लंबे समुद्री मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ेंगे, साथ ही माल ढुलाई की लागत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

दौसा समलेटी बम कांड : सुप्रीम कोर्ट ने हमीद की फांसी रद्द कर नए सिरे से ट्रायल का दिया आदेश

दौसा। राजस्थान के चर्चित 1996 के समलेटी (दौसा) बस बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी डॉ. अब्दुल हमीद की फांसी की सज़ा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूरे ट्रायल के दौरान आरोपी को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिली, जो निष्पक्ष सुनवाई के उसके संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने हमीद को अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि मामले में नए सिरे से ट्रायल शुरू करे और यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी की जाए। यह नया ट्रायल राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित वरिष्ठ जज की विशेष अदालत में संचालित होगा। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सह-आरोपी पप्पू उर्फ सलीम को बरी किया है। सलीम विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की उस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पांच और आगरा के एक सहित कुल छह अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। नतीजतन, इन सभी छह आरोपियों की रिहाई का निर्णय बरकरार रहा है। यह मामला 22 मई 1996 का है, जब आगरा से बीकानेर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में दौसा जिले के समलेटी गांव के पास भीषण बम धमाका हुआ था। इस भयावह घटना में 14 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 37 से अधिक लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल हमीद को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए मृत्युदंड सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद, तीन दशक पुराने इस हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले की कानूनी सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इंकार

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने से इंकार किया है, जिससे उनके लिए तात्कालिक मुश्किलें टल गई हैं।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जांच एजेंसी के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई अनावश्यक प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े कानूनी मुद्दे अभी भी विचार के लिए खुले रहने वाले है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनवरी में चैतन्य को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जमानत दी थी। इस आदेश को रद्द कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि चैतन्य को जमानत मिलने के बाद से मामले के मुख्य गवाह सामने आने से डर रहे हैं। यह मामला 2161 करोड़ के कथित शराब घोटाले से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। ईडी के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिसमें राज्य के खजाने में भारी गड़बड़ी की गई। इसके पहले 17 जून को मामले की सुनवाई टल गई थी, जब ईडी ने अतिरिक्त समय की मांग की थी। उस समय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ईडी के स्थगन मांगने पर नाराजगी व्यक्त की थी। पीठ ने टिप्पणी की थी कि पहले आप मामलों को सूचीबद्ध करने की मांग करते हैं, और फिर स्थगन मांग लेते हैं, जबकि हम इसतरह के मामलों की फाइलें रातभर पढ़ते हैं। जनवरी में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने चैतन्य को जमानत देकर कहा था कि उन पर आबकारी विभाग या राज्य की शराब निगमों में किसी आधिकारिक पद पर रहने का आरोप नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ आरोप मुख्य रूप से पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और अन्य आरोपियों से कथित संबंधों पर आधारित हैं। ईडी ने उन्हें जुलाई 2023 में इस कथित घोटाले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था।

राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर फैसला टला, अब 2 सितंबर को होगी अगली बैठक

नई दिल्ली । अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में नई नियुक्तियों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ट्रस्ट ने तय किया है कि नए न्यासियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति सहित अन्य लंबित मुद्दों पर अब 2 सितंबर को होने वाली अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान ट्रस्ट ने बैंक के साथ हुए एक करार में सामने आई अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। ट्रस्ट सदस्यों ने इस समझौते की दोबारा समीक्षा करने पर जोर दिया और कहा कि मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में लगाए गए सुरक्षा कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, जिस पर ट्रस्ट ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। इस प्रतिष्ठित पद के लिए देशभर से हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कई सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया अभी जारी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। ट्रस्ट ने यह भी निर्णय लिया कि मंदिर से जुड़ी सूचनाओं और आधिकारिक जानकारी के बेहतर संप्रेषण के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, महासचिव कृष्ण मोहन अपने वर्तमान दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। अब सभी की निगाहें 2 सितंबर को होने वाली अगली बैठक पर हैं, जिसमें नई नियुक्तियों समेत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले लिए जाने की संभावना है।

चरणजीत सिंह चन्नी पर कांग्रेस की दुविधा, पंजाब में भाजपा को मिल सकता है सियासी फायदा

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान अब पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने फिलहाल नेतृत्व में बदलाव से इनकार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह असंतोष बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी नाराजगी पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने से राज्य के प्रभावशाली जाट सिख मतदाताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है और अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। इस बीच पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने खुलकर चरणजीत सिंह चन्नी को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया है। उनका कहना है कि भाजपा में उन्हें सम्मान और समाज के सभी वर्गों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस छोड़ते हैं, तो विशेष रूप से दोआबा क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि दलित समुदाय में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी केवल पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के प्रमुख दलित चेहरों में से एक हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जालंधर सीट पर बड़ी जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की थी। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह संगठनात्मक एकता बनाए रखे, जबकि भाजपा इस असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। यदि विवाद लंबा खिंचता है, तो आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।

नीट पेपर लीक आंदोलन : दिल्ली में आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के 98 स्थानों पर प्रदर्शन, पुलिस ने 14 दिन तक की डिजिटल निगरानी

मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को देशभर से समर्थन मिल रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में भी छात्रों और युवाओं ने सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन किए। वहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी व्यापक नाराजगी देखने को मिली। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 दिनों तक विशेष डिजिटल पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आंदोलन की संभावनाओं को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखी गई। आंदोलन से जुड़े हैशटैग, की-वर्ड्स और लगातार पोस्ट करने वाले अकाउंट्स की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। आंदोलन का समर्थन करने वाले और उसके प्रचार-प्रसार में सक्रिय लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस का दावा है कि इस डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए संभावित भीड़, प्रदर्शन स्थलों और आयोजकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। पुलिस ने आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई। पहले चरण में सोशल मीडिया ट्रेंड, ऑनलाइन आयोजकों और अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए खुफिया जानकारी जुटाई गई। दूसरे चरण में दादर रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख प्रवेश मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आंदोलन में शामिल होने पहुंचे कई प्रमुख लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया, जिससे बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र होने की संभावना कम हो गई। तीसरे चरण में प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाले लोगों को रोककर विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया, ताकि किसी भी स्थान पर बड़ी भीड़ जमा न हो सके। पुलिस का कहना है कि इस रणनीति के कारण किसी भी स्थान पर स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई के शिवाजी पार्क, कोल्हापुर के शिवाजी चौक, पुणे, गढ़चिरोली सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में कुल 98 स्थानों पर सीजेपी के समर्थन में आंदोलन हुए। हालांकि पुलिस का दावा है कि डिजिटल मॉनिटरिंग, खुफिया तंत्र के समन्वय और समय रहते की गई एहतियाती कार्रवाई के चलते पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनी रही और किसी भी तरह की बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई।

दिल्ली में हिंसा प्रदर्शन मामले में अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली,। दिल्ली पुलिस ने संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में हुई अलग-अलग घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। फिलहाल, मामलों की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े मामलों में संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर और सीपी थाने में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज है। इनमें से एक एफआईआर नई दिल्ली क्षेत्र में, जो एक हाई-सिक्योरिटी जोन है, संसद सत्र के दौरान बिना मंजूरी के ड्रोन उड़ाने से जुड़ी है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरएएफ जवान पर हुए हमले के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आरएएफ जवान को पीटते नजर आए। वे आरएएफ की गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ भी करते दिखे। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। साथ ही जांच टीमें उपद्रव के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए 250 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा रही है। इनमें मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे के विजुअल और पुलिस के बॉडी-वर्न कैमरों से ली गई फुटेज शामिल हैं।

बता दें सोमवार को पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने मध्य दिल्ली में संसद तक मार्च किया। जंतर-मंतर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित संसद तक मार्च करने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई। इस हिंसक प्रदर्शन में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं।

फॉरेस्ट अफसरों पर हमला और हवाई फायरिंग केस - गुजरात हाईकोर्ट से चैतर वसावा की पत्नी समेत 5 दोषियों को जमानत

अहमदाबाद। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों पर हमला, धमकी देने और हवाई फायरिंग के चर्चित मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा समेत पांच दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये पांचों मुख्य आरोपी नहीं हैं और इनके खिलाफ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के प्रत्यक्ष साक्ष्य भी सामने नहीं आए हैं। इसलिए अपील के अंतिम निपटारे तक उनकी सजा स्थगित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

यह मामला नर्मदा जिले में जमीन विवाद से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और अन्य आरोपियों ने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को घर बुलाकर उनके साथ मारपीट की, धमकाया और हवाई फायरिंग की। इस मामले में आईपीसी की धाराएं 143, 147, 149, 186, 294, 353, 386 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बाद में नर्मदा की ट्रायल कोर्ट ने चैतर वसावा, शकुंतला वसावा समेत कुल नौ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सभी दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसी दौरान शकुंतला वसावा सहित पांच दोषियों ने सजा पर रोक और जमानत की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता आई.एच. सैयद ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों की भूमिका मुख्य आरोपी जैसी नहीं थी। उनके खिलाफ किसी को चोट पहुंचाने का आरोप नहीं है। साथ ही, ट्रायल के दौरान वे जमानत पर थे और उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। इन तथ्यों को देखते हुए सजा स्थगित कर जमानत देने का अनुरोध किया गया। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि पांचों आवेदक मुख्य आरोपी नहीं हैं और उनके खिलाफ किसी को घायल करने का प्रत्यक्ष आरोप भी नहीं है। इसलिए अपील पर अंतिम निर्णय होने तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा। बचाव पक्ष का कहना था कि वन क्षेत्र में ग्रामीणों ने कपास की खेती की थी, जिसे वन विभाग ने हटाकर बाजार में बेच दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर विधायक चैतर वसावा से संपर्क किया। वन अधिकारियों के साथ बैठक में मुआवजा देने पर सहमति बनने के बाद विवाद समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई। वहीं, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि चैतर वसावा ने वन विभाग के अधिकारियों को धमकाते हुए 60 हजार रुपये का मुआवजा दिलाने का दबाव बनाया, हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी और अपने निर्माणाधीन मकान से रिवॉल्वर मंगाकर हवाई फायरिंग की। आरोप यह भी है कि वन विभाग के कर्मचारियों को धमकाकर उनके बैंक खातों से एटीएम के जरिए रुपये निकलवाकर किसान को भुगतान कराया गया था।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच का दायरा बढ़ा

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब इसकी आंच लखनऊ तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां आरोपियों और उनके परिवार के 54 सदस्यों की संपत्तियों का ब्योरा जुटाने में लगी हैं। लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण , आवास विकास परिषद, स्टाम्प विभाग और राजस्व विभाग से पिछले 2 सालों में खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान और अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया है।

जानकारी के मुताबिक गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखनऊ समेत कई जिलों में आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। अयोध्या पुलिस ने जिलों के डीएम से जमीन और संपत्तियों के दस्तावेज मांगे हैं। आरोपियों और उनके परिवार के 54 सदस्यों की संपत्तियां जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों से शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदी गई कृषि भूमि की भी पूरी जानकारी मांगी है।

मकान, प्लॉट और दुकानों की जांच

जानकारी के मुताबिक संपत्तियों की जांच को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रदीप वर्मा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसके तहत मकान, प्लॉट और दुकानों के अलावा कृषि वाली जमीनों की जांच की जा रही है। इसके लिए जिले के सभी उपजिलाधिकारियों और सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प प्रथम व द्वितीय को भी पत्र भेज गया है।

रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू

यह जांच अयोध्या के स्स्क के पत्र के आधार पर शहर में कराई जा रही है। पत्र मिलने के बाद लखनऊ प्रशासन ने विभिन्न विभागों को सक्रिय करते हुए रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विभागों से प्राप्त जानकारी को एकत्र कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आगे की जांच के लिए संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा।

बेनामी संपत्तियां खरीदने का शक

अयोध्या पुलिस को शक है कि चढ़ावे की चोरी से मिली रकम से आरोपितों ने लखनऊ में बेनामी संपत्तियां खरीदी हों। अधिकारियों का कहना है कि संपत्तियों का ब्योरा मिलते ही उसकी वैधता की भी जांच की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर तीनों विभागों से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज गैलरी

खेत से लौटे 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत

तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी निवासी 25 वर्षीय युवक नंदकिशोर पिता सोहनलाल उपवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 22 जुलाई की सुबह खेत से लौटने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे पहले खैरलांजी के शासकीय अस्पताल ले गए।जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदकिशोर अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन हैं। सभी की शादी हो चुकी है और सभी एक साथ रहते हैं। बताया गया कि 22 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे वह अपने खेत देखने गया था। करीब 9 बजे घर लौटने के बाद उसने अपनी मां गिरिजाबाई से तबीयत खराब होने, चक्कर आने और अच्छा महसूस नहीं होने की शिकायत की। इसके बाद परिजन उसे तत्काल खैरलांजी अस्पताल लेकर पहुंचे।जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की तथा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच के लिए खैरलांजी पुलिस थाना भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही नन्दकिशोर की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

30 साल तक दबाकर रखी गई 60 करोड़ की वसीयत, चार ट्रस्टों ने लगाए अनिल कांकरिया पर गंभीर आरोप

राम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट और अग्रवाल समाज ने संयुक्त प्रेसवार्ता में किया बड़ा खुलासा, बोले स्व. मोहनलाल माहेश्वरी की अंतिम इच्छा को दबाकर संपत्तियां बेची गई, ट्रस्टों को नहीं मिला एक रुपया

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

शहर में बुधवार को उस समय एक बड़ा विवाद सामने आया, जब राम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट तथा अग्रवाल समाज बालाघाट के पदाधिकारियों ने स्थानीय सर्किट हाउस में संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित कर करीब तीन दशक पुरानी वसीयत को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ट्रस्टों के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने वर्ष 1996 में अपनी अंतिम वसीयत के माध्यम से स्पष्ट इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि चारों ट्रस्टों को दी जाए, लेकिन इस वसीयत को करीब 30 वर्षों तक दबाकर रखा गया और उनकी अंतिम इच्छा को जानबूझकर अमल में नहीं लाया गया।

प्रेसवार्ता में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी सुरेश सोनी सहित चारों ट्रस्टों के प्रतिनिधि एवं इस प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता वर्णन श्रीवास्तव मौजूद रहे। उन्होंने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि स्व. मोहनलाल माहेश्वरी ने 16 अगस्त 1996 को अपनी विधिवत वसीयत तैयार की थी। इस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति किसी रिश्तेदार या निजी व्यक्ति को देने के बजाय उसे बेचकर प्राप्त धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट तथा अग्रवाल समाज को देने की इच्छा व्यक्त की थी। ट्रस्ट पदाधिकारियों का आरोप है कि स्व. माहेश्वरी ने यह वसीयत एक बंद लिफाफे में

सुरजमल बोहरा को सौंपी थी और निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद यह लिफाफा अनिल कांकरिया को सौंप दिया जाए, ताकि वसीयत के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके। उनका कहना है कि अब विधिक नोटिसों के जवाब में स्वयं सुरजमल बोहरा और अनिल कांकरिया ने स्वीकार किया है कि वसीयत उनके कब्जे में थी, जिससे यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि जब वसीयत उपलब्ध थी तो उसका निष्पादन लगभग 30 वर्षों तक क्यों नहीं किया गया। प्रेसवार्ता में अधिवक्ता वर्णन श्रीवास्तव ने कहा कि यदि वसीयत वर्ष 1996 से अस्तित्व में थी और संबंधित लोगों के पास सुरक्षित थी, तो कानून के अनुसार उसका निष्पादन तत्काल होना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत वसीयत को सार्वजनिक नहीं किया गया और ट्रस्टों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान संबंधित संपत्तियों का विक्रय और हस्तांतरण किया गया तथा उससे प्राप्त आर्थिक लाभ ट्रस्टों तक नहीं पहुंचाया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी की अंतिम इच्छा को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया और उनकी संपत्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया। उनका दावा है कि संबंधित संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि यह राशि वसीयत के अनुसार ट्रस्टों को मिलती, तो उससे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का व्यापक विस्तार किया जा सकता था। लेकिन कथित रूप से ऐसा नहीं होने से समाज और ट्रस्ट दोनों को भारी आर्थिक क्षति हुई। प्रेसवार्ता के दौरान ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यह मामला केवल संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि दिवंगत व्यक्ति की अंतिम इच्छा, धार्मिक आस्था और समाज के विश्वास से जुड़ा विषय है। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति की विधिवत बनाई गई वसीयत को वर्षों तक छिपाकर रखा जाता है और उसके विपरीत संपत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो यह गंभीर कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। चारों ट्रस्टों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि वे जल्द ही संबंधित दस्तावेजों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर अनिल कांकरिया एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन देंगे। साथ ही न्यायालय के समक्ष भी पूरे प्रकरण को मजबूती से रखा जाएगा, ताकि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी की अंतिम इच्छा का सम्मान हो सके और यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसके दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मिरगपुर में तीन सराफा दुकानों में लाखों की चोरी

सीसीटीवी में कैद हुआ चोर, सोने चांदी के आभूषण और नगदी पर किया हाथ साफ, पुलिस ने फुटेज के आधार पर शुरू की आरोपियों की तलाश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मिरगपुर में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने तीन ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जुलाई की रात 9 बजे करीब मिरगपुर बाजार क्षेत्र की सभी दुकाने बन्द कर दुकान के दुकानदार घर चले गए थे। 22 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों ने बाजार क्षेत्र में जेवरात की दुकानों के टूटे ताले और खुले शटर देखे।जिसके बाद संबंधित दुकानदारों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने पर लक्ष्मी ज्वेलर्स, गौरव ज्वेलर्स और आर्ष ज्वेलर्स में चोरी की घटना सामने आई।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लक्ष्मी ज्वेलर्स और गौरव ज्वेलर्स से सोने-चांदी के आभूषणों के साथ नगदी भी चोरी हुई है। जबकि आर्ष ज्वेलर्स से मरम्मत के लिए रखे गए पुराने आभूषण चोर अपने साथ ले गए। वहीं एक अन्य दुकान का ताला भी तोड़ा गया। लेकिन वहां से चोर कोई सामान नहीं ले जा सके। यह चोरी 21 एवं 22 जुलाई की दरमियानी रात में हुई। इस चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में एक युवक दुकान के भीतर चोरी करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही तिरोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर जांच शुरू कर दी। इधर ग्राम पंचायत मिरगपुर के सरपंच दीपक देशमुख ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस गश्त की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो व्यापारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तिरोड़ी थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पिता-पुत्र घायल

दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों पिता पुत्र

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। नगर के गोंदिया रोड स्थित अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच कृष्णा डेयरी के पास मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घायलों को डायल 112 की सहायता से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया ।दोनो घायल कन्नू पिता लक्ष्मीचंद सोनी 45 एवं उनके पुत्र सिद्धांत सोनी 14 निवासी नगर के वार्ड क्र. 6 बैहर चौकी, बालाघाट निवासी है दोनों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्नू सोनी की एलआईसी चौक अंबेडकर चौक के समीप गुपचुप एवं चाट की दुकान है। 21 जुलाई की रात करीब 12 बजे दुकान बंद करने के बाद कन्नू सोनी अपने पुत्र सिद्धांत के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गोंदिया रोड पर कृष्णा डेयरी के सामने विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों स्कूटी सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। जिला अस्पताल में दोनों का उपचार जारी है। वहीं दुर्घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

चार दिन बाद सकुशल मिली नाबालिग किशोरी

डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी रिश्तेदारी में, पुलिस की सक्रियता से गुमशुदगी का मामला सुलझा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। चांगोटोला पुलिस ने चार दिन से लापता नाबालिग किशोरी को सकुशल दस्तयाब कर गुमशुदगी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह माता पिता की डांट से नाराज होकर अपनी मर्जी से रिश्तेदारों के घर चली गई थी। उसे किसी ने बहला-फुसलाकर नहीं भगाया था और न ही उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई। जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को किशोरी के परिजनों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर गुम इंसान कायम करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की और सभी थाना-चौकियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेजी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में पुलिस थाना चांगोटोला की प्रभारी निरीक्षक मांगीलाल भाटी के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार तलाश करते हुए 22 जुलाई को किशोरी को उसके रिश्तेदार के घर से ही सकुशल दस्तयाब कर लिया गया।महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की गई पूछताछ में किशोरी ने बताया कि घर और खेत के काम में सहयोग नहीं करने पर माता-पिता द्वारा डांट फटकार लगाने से वह नाराज हो गई थी। इसी कारण वह अपनी इच्छा से रिश्तेदारों के घर चली गई थी। जहां वह सुरक्षित रह रही थी। उसने स्पष्ट किया कि उसे किसी ने बहला-फुसलाकर नहीं ले गया और न ही उसके साथ कोई गलत घटना हुई। जांच के दौरान परिजनों एवं रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए गए। जिनमें किशोरी के कथनों की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिए।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

मामले के त्वरित निराकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक मांगीलाल भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम के सहायक उप निरीक्षक ग्लैडविन छतरिया, प्रधान आरक्षक अशोक खंडाते, प्रधान आरक्षक मुकेश उइके, आरक्षक नरेश भंडारी, आरक्षक अखलेश्वर पंचेश्वर, आरक्षक राकेश मीणा के साथ महिला पुलिसकर्मी आरक्षक रजनी नगपुरे, एस एस यू कर्मचारी अर्चना सोनवाने, निशिका पांचे, पूजा साहू, विक्रांत बाहे और देवेंद्र सिरसाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से किशोरी को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया।

आवश्यकता है
क्वार्क में पेज सेटिंग हेतु
कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता है
संपर्क करें-बालाघाट एक्सप्रेस
पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :**9425138710**, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट